



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 23, 1982/ माघ 3, 1903

No. 17]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 23, 1982/MAGHA 3, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

## वाणिज्य मंत्रालय

### आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 5-आई टी सी(पीएन)/82

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1982

विषय :—जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (फो ई सी एक)  
द्वारा प्रदान किए गए तमिल नाडु राज्य बिजली बोर्ड (टी एन एस  
ई बी) के लोअर मेट्रूर हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना के कार्यान्वयन के  
लिए येन 7.6 बिलियन येन ऋण के अधीन माल और सेवाओं के  
आयात के संबंध में लाइसेंस शर्तें।

फा० सं० आई० पी० सी०/23/(24)/81.—जापान की विदेशी  
आर्थिक सहयोग निधि द्वारा प्रदान किए गए तमिल नाडु  
राज्य बिजली बोर्ड के लोअर मेट्रूर हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना  
के कार्यान्वयन के लिए येन 7.6 बिलियन येन ऋण के अधीन  
माल और सेवाओं के आयात के सम्बन्ध में आयात लाइसेंस जारी करने से  
सम्बन्धित लागू होने वाली शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट  
में दी गई हैं, उन्हें जानकारी के लिए अधिगृहित किया जाता है।

वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं० 5-आई टी सी(पी एन)/82

23 जनवरी, 1982 का परिशिष्ट

तमिल नाडु राज्य बिजली बोर्ड (टी० एन० एस० ई० बी०) की लोअर  
मेट्रूर हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 7.6 बिलियन येन

के ऋण के अन्तर्गत माल और सेवाओं के आयात के संबंध में लाइसेंस  
शर्तें।

### खंड -1 सामान्य शर्तें

1 (1) तमिल नाडु राज्य बिजली बोर्ड (टी एन एस ई बी) लोअर  
मेट्रूर हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना की आयात आवश्यकताओं को निर-  
धान करने के लिए जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (फो ई सी  
एक) द्वारा प्रदान किया गया 7.6 बिलियन येन का ऋण भारत और  
जापान सहित अन्य विकासशील देशों के लिए खुला है। तदनुसार, इस  
क्रेडिट के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं जापान  
और अनुबन्ध 1 की सूची में उद्धृत सभी देशों से आयात की जा सकती  
हैं। ये देश इस ऋण के अन्तर्गत पात्र स्टोन देश होंगे।

1 (2) क्रेडिट के अधीन केवल उन्हीं मर्चों और उसी मूल्य के लिए  
लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं जिनके लिए महाविदेशालय, त्रुनांकी  
विकास/पूँजीगत माल समिति द्वारा विशेष रूप से निकासी करवाई गई हों।  
इस क्रेडिट के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंस(सों) का मूल्य  
येन 8,500 मिलियन (आठ-बीस-भाई) येन से अधिक नहीं होना  
चाहिए।

आयात लाइसेंस का रुपये में मूल्य, राजस्व विभाग (सीमा-शुल्क)  
द्वारा अधिसूचित विनियम वर और आयात लाइसेंस जारी करने की तिथि  
को प्रचलित वर और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी की गई  
सार्वजनिक सूचना सं० 78-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 6 जून,  
1974 के पैरा-2 के अनुसार आयात लाइसेंस में संकेतित वर पर निर्धारित  
किया जाएगा, जिसमें यह उल्लेख है कि सीमा-शुल्क प्राधिकारी और

विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी आयात लाइसेंस(सों) में विनिर्दिष्ट मुद्रा विनिमय दर पर लाइसेंस मूल्य के नामे डालेंगे। लाइसेंस पर एक शीर्षक "जापानी येन ऋण सं० आई बी पी-14" होगा। प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस में "एम/जे सी" कोड होगा। टी एन एम ई बी को आयात लाइसेंस भेजने समय मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के पत्र में भी इसे दुहराया जाएगा, जिसकी एक प्रति वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को पृष्ठांकित की जानी चाहिए।

1 (3) लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर केवल (टी एन एम ई बी) के नाम में लाइसेंस जारी किया जा सकता है।

1 (4) टी एन एम ई बी की सुविधा पर निर्भर करते हुए एक से अधिक आयात लाइसेंस इन श्रेष्ठ के अधीन जारी किए जा सकते हैं। लेकिन, कुल मूल्य येन 8,500 मिलियन (लागत-बीमा-भाड़ा) येन से अधिक नहीं होना चाहिए जैसा कि ऊपर पैरा (1) में कहा गया है।

1 (5) आयात लाइसेंस की वैधता में वृद्धि (टी एन एम ई बी) द्वारा आवेदन करने पर 31-3-86 तक दी जा सकती है। इससे भागे की वृद्धि यदि कोई हो तो उसके लिए आवेदन आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेजा जाना चाहिए।

1 (6) क्रेडिट के अधीन वित्त दान किए जाने वाले आयात, आयात लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विधिवत मस्थापित संलग्न माल और सेवाओं की सूची तक प्रतिबंधित है।

1 (7) विदेशी मुद्रा के किसी भी परेषण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी। भारतीय अधिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान भारतीय अधिकर्ता को भारतीय रुपये में किया जाना चाहिए। लेकिन, ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और इसलिए लाइसेंस पर ही प्रभावित किए जाएंगे।

1 (8) पक्के आवेदन अनुबंध-1 में उल्लिखित वेगों में स्थित विदेशी संभरकों को जहाज पर निःशुल्क को आधार पर दिए जाने चाहिए और वे आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीनों की अवधि के भीतर आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेज दिए जाने चाहिए। भाड़ा और बीमा प्रभाव का भुगतान भारतीय रुपये में भारत में वेय होगा। "पक्के आवेदनों" का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंस-धारी द्वारा दिए गए उन न्युन आवेदनों से है जो विदेशी संभरक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हों या भारतीय आयातक और विदेशी संभरक दोनों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित न्युन संविदा हो। विदेशी संभरकों के भारतीय अधिकर्ताओं के आवेदन या ऐसे भारतीय अधिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण आवेदन स्वीकार्य नहीं है।

1 (9) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि के चार महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग डब्ल्यू० ई०-1 अनुभाग को नहीं पहुंच जाते हैं। यदि उपर्युक्त पैरा 1 (8) में तथा उल्लिखित पक्के आवेदन चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आवेदन क्यों नहीं दिए जा सकते इन कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस को सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए। आवेदन देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा। वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 8 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसको वे

लाइसेंसधारी को प्रेषित करेंगे। लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्राधिकारियों से केवल ऐसी वृद्धि प्रदान करने वाला एक पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकृत व्यापारी और विभागीय प्राधिकारी, आयात लाइसेंस के अधीन किए गए संभरण ठेकों में बैंक गारंटी साख पत्र स्थापित करने के लिए प्राधिकार पत्र तुरंत रूपया जमा कराने आदि की स्वीकृति की सुविधाओं की अनुमति देंगे।

1 (10) आयात लाइसेंस का समाप्ति से चार महीने के भीतर सभी भुगतान अवश्य पूर्ण कर देने चाहिए। मांग के पोललदान दर अलग-अलग भुगतानों की व्यवस्था होनी चाहिए। ठेके में नकद आधार पर अर्थात् पोललदान दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए। विदेशी संभरक से भारतीय आयातक को किसी भी किस्म की ऋण सुविधा उपलब्ध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मांग के वितरण की अवधि के लिए ठेके में निम्नलिखित अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए :—

"साख-पत्र की प्राप्ति के बाद ..... महीने परन्तु अधिक से अधिक ..... के अन्त तक पूर्ण किया जाना है।

पोललदान के लिए आखिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह तिथि 31-3-86 के बाद की न हो।

पृष्ठ -2 सम्भरण ठेके का समीक्षा करते समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें :

2 (1) ठेके का जहाज पर्यंत निःशुल्क मूल्य येन में (येन की भिन्न के बिना) अभिव्यक्त होना चाहिए और इसमें भारतीय अधिकर्ता का कमीशन, यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रुपये में चुकाना चाहिए।

भारतीय रुपये या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। न्युन आवेदन और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आवेदन केवल अंग्रेजी में होना चाहिए।

2 (2) ओ० ई० सी० एफ० येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) के अधीन माल और सेवाएं अधिप्राप्त करने के लिए विस्तृत निर्देश अनुबंध-2 में दिए गए हैं। लेकिन, साधारणतया माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति औपचारिक खुली अंतर्राष्ट्रीय संविदा के माध्यम से की जानी चाहिए और निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए :—

(क) बोली लगाने के लिए नियंत्रण भारत में सामान्य रूप से परिचलित होने वाले कम से कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित करने पड़ेंगे।

(ख) बोली के बांड या बोली लगाने की गारंटी की सामान्य आवश्यकता है, परन्तु वह इतनी उंची नहीं होनी चाहिए कि उचित बोली लगाने वाले, हतोत्साहित हो जाएं।

(ग) बोली खुल जाने के बाद असफल बोलीकारों को यथाशीघ्र बोली वापस या गारंटियां रिहा कर देनी चाहिए।

2 (3) जिन मामलों में औपचारिक खुली अंतर्राष्ट्रीय निविदा उचित न हो वहाँ निधि निम्नलिखित वैकल्पिक विधायिधि अपनाएंगी :—

(क) जहाँ आयातक के पास विश्वसनीय कारण हों या अपने उपस्कर का उचित मानकीकरण रखा हो।

(ख) जहाँ पर पात्र संभरकों की संख्या सीमित हो।

(ग) जहाँ अधिप्राप्ति में शामिल अनराजि इतनी कम हो कि विदेशी फर्म स्पष्ट रूप से विश्वस्पी न ले या औपचारिक खुली अंतर्राष्ट्रीय संविदा के फायदे शामिल प्रशासकीय भार से महत्वपूर्ण हो।

(घ) ऊपर (क), (ख) और (ग) के प्रतिरुध जहाँ निधि औपचारिक खुली अंतर्राष्ट्रीय निविदा का अनुकरण करना अनुचित

समझे या निम्न ऐसी प्रक्रिया का अनुयुक्त समझे उदाहरणार्थ आपात अधिप्राप्ति के मामले में ।

उपर संकेतिक मामलों में निम्नलिखित अधिप्राप्ति प्रक्रिया इस ढंग से अपनाई जाए जिससे जहाँ तक उचित हो पूर्ण सम्भाव्य सीमा तक औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया का अनुपालन हो सके :-

- (1) औपचारिक चुनिन्दा अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करना ।
- (2) अनीपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक अधिप्राप्ति ।
- (3) एक संभरक से सीधा क्रय ।

टी एन एस ई पी को चाहिए कि वे तत्काल ही बोलीकारों की तीन प्रतियों में सभी सूचनाओं और अनुदेशों, बोली प्रपत्र, प्रस्तावित संविदा विनिर्दिष्टियों और ड्राइंग, बोली लगाने की विनियमन की रिपोर्ट, प्रचारी के लिए प्रस्ताव और बोली लगाने सम्बन्धित सभी अन्य दस्तावेजों की प्रतियाँ वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेज दें जो ऋण समझौते की अनुसूची 5 के पैरा 1 (2) में किए गए के अनुसार इसकी परीक्षा के लिए इन दस्तावेजों को प्रो० ई० सी० एफ० भेजेंगे ।

2 (4) विदेशी संभरक का भुगतान, उनके नाम में भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा 1981-82 के लिए प्रो० ई० सी० एफ० येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं० आई डी पी-14 के अधीन खोले गए अपरिवर्तनीय साख-पत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए जिसका ब्यौरा नीचे खण्ड-6 में दिया गया है ।

2 (5) आयात लाइसेंस के प्रतिकेवल एक ही संविदा की जानी चाहिए । लेकिन, कुछ विशेष मामलों में, एक से अधिक संविदा करने की अनुमति भी दी जा सकती है जिसके लिए आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि के तुरन्त बाद वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) से अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए ।

#### 2 (6) संभरक की पात्रता

संभरक पात्र स्त्रोत देशों के राष्ट्रिक होंगे या पात्र स्त्रोत देशों में शामिल किए गए तथा पंजीकृत किए गए पात्र स्त्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा शासित वैध व्यक्ति होंगे ।

#### 2 (7) संविदा में घोषणा

प्रत्येक संविदा में संभरकों द्वारा पात्रता का निम्नलिखित विवरण जोड़ा जाएगा :-

“मैं, अधोहस्ताक्षरी एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि सभारित किया जाने वाला माल ----- में (पात्र स्त्रोत देश) उत्पादित है ।

मैं, अधोहस्ताक्षरी भोगे यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार अपात्र स्त्रोत देशों से आयातित भाग निम्नलिखित सत्र के अनुसार 30 प्रतिशत से कम है :-

आयातित लागत-सीमा भाड़ा मूल्य + आयात शुल्क  
----- × 100”  
संभरक का जहाज पर निःशुल्क मूल्य

और

“मैं, अधोहस्ताक्षरी, एतद्वारा सत्यापित करता हूँ कि ----- (पात्र स्त्रोत देश का नाम) में ----- (कम्पनी का नाम) समाविष्ट और पंजीकृत हो चुकी है और पात्र स्त्रोत देश के राष्ट्रिकों द्वारा नियंत्रित है ।”

#### 2 (8) अपात्र स्त्रोत देशों से अनुमेय आयात

जिन वस्तुओं में अपात्र स्त्रोत देशों में बनी हुई सामग्री निहित है उनका बितरण किया जा सकता है बशर्ते कि निम्नलिखित सूत्र के अनुसार पर-

वार आधार पर आयातित भाग 30 प्रतिशत से कम हो :-

आयातित लागत-सीमा-भाड़ा मूल्य + आयातक शुल्क  
----- × 100  
संभरक का जहाज पर निःशुल्क मूल्य

खण्ड 3. संभरण ठेकों से समाविष्ट की जाने वाली शर्तें

3 (1) संभरण ठेकों में निम्नलिखित प्रावधान विशेष रूप से समाविष्ट होने चाहिये :-

(क) ठेके की व्यवस्था भारत सरकार और जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (प्रो ई सी एफ) के बीच टी एन एस ई बी लोअर मेट्रूर हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना के लिए येन क्रेडिट आई डी पी-14 (परियोजना सहायता) से सम्बन्धित 15 अक्टूबर, 1981 को हुए ऋण समझौते के अनुसार होनी चाहिए और यह भारत सरकार और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के अनुमोदन के अधीन होगा ।

(ख) संभरकों को भुगतान, भारत सरकार और जापानी विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (प्रो ई सी एफ) के बीच येन क्रेडिट सं० आई० डी० पी० 14 सम्बन्धित 15 अक्टूबर, 1981 को हुए ऋण समझौते के अन्तर्गत बैंक आफ इण्डिया टोकियो द्वारा जारी किए जाने वाले अपरिवर्तनीय साखपत्र के माध्यम से किए जाएंगे ।

(ग) विदेशी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक और भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर प्रो ई सी एफ द्वारा येन ऋण के अधीन अपेक्षित हों ।

(घ) 2 (7) में उल्लिखित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र (तीन प्रतियों में)

3 (2) यदि किसी मामले में संभरक जापान में स्थित हो तो संभरण संविदा के संबंध में एक धारा होनी चाहिए कि जापानी संभरक भारतीय दूतावास, टोकियो के परामर्श पर पोत परिवहन व्यवस्था, करने के लिए सहमत है और इस उद्देश्य के लिए वह भारतीय दूतावास टोकियो को, शामिल माल की मुपुर्वाग के कार्यक्रम से प्रवगत कराएगा और पोत लदान से कम से कम 6 महीने पूर्व भारतीय दूतावास को सूचना देगा जिससे कि उचित व्यवस्था हो सके । विशेष मामलों में, जहाँ भारतीय आयातक इच्छुक हों, सूचना की इस अवधि को कम किया जा सकता है । जापानी संभरक को प्रत्येक पोतलवान के पश्चात् आवश्यक ब्यौरे देते हुए तार से सूचना भेजने के लिए सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास टोकियो को भेजी जानी चाहिए ।

खण्ड-4 विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (प्रो० ई० सी० एफ०) द्वारा ठेके का अनुमोदन ।

4 (1) लाइसेंसधारी को पक्के आदेश देने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर टी एन एस ई बी और विदेशी संभरकों दोनों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित ठेके की वार प्रतियाँ जो विदेशी संभरकों द्वारा लिखित में पुष्टि आदेश के साथ हों या उनकी हर प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियाँ संगत वैध आयात लाइसेंस की दो फोटो प्रतियों सहित जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए ।

4 (2) उपर्युक्त क्रियाविधि सभी ठेकों के लिए और ठेकों की विषय वस्तु के लिए अनिवार्य आशोधनों के कारण संशोधनों या उनकी कीमतों पर भी लागू होगी ।

4 (3) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) जापान अनुभाग, टी एन एस ई बी के लोअर मेट्रूर हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना के लिए येन क्रेडिट सं० आई डी पी-14 परियोजना सहायता के अन्तर्गत वित्त-दान करने के लिए विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (प्रो ई सी एफ) को संविदा दस्तावेजों की एक प्रति उनके अनुमोदन के लिए भेजने की व्यवस्था करेगा ।

**खण्ड-5 विदेशी संभरकों को भुगतान साख-पत्र क्रियाविधि**

5 (1) विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (ओ ई सी एफ) से ठेके के अनुमोदन की सूचना मिलने पर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, आपन अनुभाग द्वारा टी एन एम ई बी और सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, को उसकी सूचना दे दी जाएगी। उसके बाद टी एन एम ई बी को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक (जिसे इसके बाद सी० ए० ए० एण्ड ए० कहा गया है) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, संवद मार्ग, नई दिल्ली को अनुबन्ध-3 के रूप में संलग्न प्रपत्र में प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध करना चाहिए। सी० ए० ए० एण्ड ए० संबंधित विदेशी संभरक के लिए संलग्न प्रपत्र-4 में एक प्राधिकार पत्र जारी करेगा। जो सम्बद्ध विदेशी संभरक के नाम में (वास्तविक आयातों के लिए संलग्न अनुबन्ध-5 के रूप में या (सेवाओं के लिए) अनुबन्ध-6 के रूप में अपरिचालनीय साख-पत्र खोलने के लिए भारतीय बैंक की टोकियो शाखा को भेजा जाना चाहिए। प्राधिकार पत्र की प्रतियाँ (विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि ओ ई सी एफ) भारतीय दूतावास, टोकियो भारत में आयातक के बैंक और आपन अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भी पृष्ठांकित की जाएगी।

5 (2) प्राधिकार पत्र मिलने पर, भारतीय बैंक, टोकियो अनुबन्ध-5 (वास्तविक आयातों के लिए लागू होता है) या 6 (सेवाओं के लिए लागू होता है) के अनुसार सम्बन्धित विदेशी संभरकों के नाम में अपरिचालनीय साख-पत्र की स्थापना करेगा और उसकी एक प्रति विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (ओ ई सी एफ) भारतीय दूतावास, टोकियो भारत में आयातक के बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, को भी भेजेगा।

सी० ए० ए० एण्ड ए० से प्राधिकार पत्र के आधार पर साख-पत्र खोलने के लिए उपर्युक्त क्रिया-विधि संविदा संगोपन या अन्यथा के लिए आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे सभी प्राधिकार पत्र/साख-पत्रों के संगोपनों पर स्वतः लागू होगी।

5 (3) माल का पोतलवान करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकों के माध्यम से साख-पत्र में उल्लिखित दस्तावेज भुगतान के लिए बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इण्डिया, टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि को विदेशी संभरक को उसके बैंकों के माध्यम से रिहा करेगा और उसके बाद आयातों की लागत की धनराशि की प्रतिपूर्ति विदेशी आर्थिक निधि से प्राप्त करेगा।

5 (4) साख-पत्र के अन्तर्गत सौदे तय करने के लिए साख-पत्र खोलने के लिए टोकियो स्थित भारतीय बैंक को चुकाने जाने वाले बैंक प्रभार और यदि कोई हो तो विदेशी संभरक के बैंक के प्रभारों के लिए विदेशी संभरक द्वारा किए जाएंगे। उनका भुगतान आयातक द्वारा नहीं किया जाएगा। विदेशी संभरक को उनके द्वारा किए गए आयातों की कीमत के, भुगतान की तिथि से, ओ ई सी एफ द्वारा प्रतिपूर्ति की तारीख तक की अवधि के लिए भरा किए जाने योग्य व्यय प्रभारों का फैसला भारत सरकार के लेखों को प्रभावित किए बिना ही सामान्य बैंकिंग सूत्र के माध्यम से टोकियो स्थित भारतीय बैंक को प्रेषण द्वारा भारत में आयातक के बैंक द्वारा किया जाएगा।

**खण्ड-6 रुपया निक्षेप करने के लिए उत्तरदायित्व**

6 (1) भारतीय बैंक, टोकियो संगत प्राधिकार पत्र के परिशिष्ट में संकेतित अनुसार आयातक के प्राधिकृत बैंक को परकाम्य जहाजरानी दस्तावेज भेजेगा और बैंक इसके बदले में यह सुनिश्चय करेगा कि जहाजरानी दस्तावेज रिहा होने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी, दिल्ली में रुपया निक्षेप कर दिया गया है। येन भुगतान के समतुल्य रुपए पर ब्याज की दर प्रथम 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक और उससे अधिक अवधि के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक होगी जो बैंक आफ इण्डिया, टोकियो द्वारा विदेशी संभरक को भुगतान तिथि में वास्तविक जमा जमा कराने की तिथि तक गिनी

जायेगी और सार्वजनिक सूचना सं० 46-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 16-6-76 के अनुसार मूल भुगतान के साथ जमा की जाएगी। यह नोट कर लिया जाना चाहिए कि दोनों दिनों अर्थात् जिस दिन विदेशी संभरक को भुगतान किया गया है और जिस दिन सरकारी लेखों में रुपया जमा किया गया है, का ध्यान लिया जाएगा। देखिए सार्वजनिक सूचना सं० 103-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 12-10-74 द्वारा यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० 74-आई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 31-5-1974।

विदेशी संभरक को किए गए येन भुगतान के समतुल्य रुपए की गणना करने के लिए अपनायी जाने वाली विनिमय की दर भुगतान की तारीख को लागू विनिमय की वह मिश्रित दर होगी जो सार्वजनिक सूचना सं० 109-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 3-8-74 और सं० 8-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 17-1-76 में निर्धारित तरीके के अनुसार निर्दिष्ट की गई हो जो मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित की गई हो। जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया निक्षेप किया जाएगा वह "के डिपोजिटर्स एंड एडवांसिज-843 निविन डिपोजिटर्स—डिपोजिटर्स फार पर-चेजिज एस्टिमा एमोड अंडर क्रेडिट्स लोन एग्रीमेंट" लोन फ्रॉम दो गवर्नमेंट आफ जापान 7 बिलियन येन क्रेडिट सं० आई डी पी-14 फार लोन्स मेट्रूर हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना होना चाहिए।

6 (2) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी दिल्ली में सरकार की साख में सार्वजनिक सूचना सं० 184-आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 30-8-68, सं० 233-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 24-10-68, सं० 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71, सं० 74-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-74 और सं० 103-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित तरीके में जमा होना चाहिए।

6 (3) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद मात दिनों के भीतर सम्बद्ध भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित व तरीके से वह अनिवार्य धनराशि से या खर्चों के निमित्त भेजेगा जो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा मांगी जाए। चालान के विभिन्न कालों को भरते समय आयातकों/उनके बैंकों को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं० 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-1971 के पैरा-2 में निर्धारित सूचना चालान के काल में "धन परेषण और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण व्योरे" में निरपवाद रूप से निदिष्ट किए गए हैं। खजाना चालान में निम्नलिखित व्योरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए।

(क) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र संख्या और दिनांक।

(ख) येन मुद्रा की वह धन राशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाने हैं।

(ग) विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि।

उसके पश्चात् सी० ए० ए० एण्ड ए० द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र का संदर्भ देते हुए और धीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों को संलग्न करते हुए खजाना चालान रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी० ए० ए० एण्ड ए० को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी: भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चय करना चाहिए कि रुपए का निक्षेप भारतीय बैंक, टोकियो की प्रदायगी की सूचना और अपरिचालनीय पोतलवान दस्तावेजों की प्राप्ति 10 दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सी० ए० ए० एण्ड ए० वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा।

6(4) भारत में सम्बद्ध भारतीय बैंक को लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति पर कपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित "एस" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक, अम्बई को भेजना चाहिए।

#### खंड 8 विविध व्यवस्थाएं

##### 8(1) आयात लाइसेंस के उपयोग करने की रिपोर्ट

आयातक का पोतलदान और उसके अधीन किए गए भुगतान और शेष धनराशि के बारे में साप्ताहिक खोलने के बाद एक मासिक रिपोर्ट सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, संवाद मार्ग नहीं दिल्ली को भेजनी चाहिए।

##### 8(2) संभरकों को विशेष शर्तों के बारे में अधिसूचित करना

लाइसेंसधारी के आयात लाइसेंस में दिए गए किसी उन विशेष उपबन्धों से संभरक को प्रयोग करा देना चाहिए जो माल के लाने में संभरक पर प्रभाव डालती है।

##### 8(3) विवाद

यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंस और संभरकों के बीच कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। भारतीय बैंक टोकियो द्वारा किए गए भुगतान से पहले संभरक द्वारा पूर्ण की जाने वाली शर्तों अनुबंध 3 में "भुगतान की शर्त" के अन्तर्गत अच्छी तरह से स्पष्ट कर लेनी चाहिए। संविदा की शर्तों में विवाद के निपटान से सम्बद्ध व्यवस्थाएं शामिल होनी चाहिए।

##### 8(4) मजिष्य अनुदेश

आयात लाइसेंस या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों से संबंधित या जापानी प्राधिकारियों के साथ येन क्रेडिट समझौते (परियोजना सहायता) सं० आई डी पी-14 के अधीन सभी आभारों को विशेषी आर्थिक निगम निधि, जापान (ओ०ई०सी०एफ०) के साथ पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों, अनुदेशों या आवेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा।

##### 8(5) प्रतिक्रमण या उत्संधन

उपर्युक्त खंडों में निर्धारित की गई शर्तों के प्रतिक्रमण या उत्संधन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

##### 8(6) अनुबंधों की सूची

1. अनुबन्ध-1 पात्र खेत देशों की सूची
2. अनुबन्ध-2 अधिप्राप्ति के लिए मुख्य मार्ग दर्शन
3. अनुबन्ध-3 अधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध
4. अनुबन्ध-4 प्राधिकार पत्र का प्रपत्र
5. अनुबन्ध-5 साख पत्र का प्रपत्र (वास्तविक आयातों के लिए लागू)
6. अनुबन्ध-6 साख पत्र का प्रपत्र (सेवाओं के लिए लागू)

अनुबंध 1

#### पात्र खेत देशों की सूची

- (क) विकासशील देश तथा उसके क्षेत्र  
(क-1) ओ०पी०ई०सी० से मिला विकासशील देश

##### 1. अफ्रीका उत्तरी सहारा

मिथ  
मोरोको  
सुदीनिया

अफ्रीका दक्षिणी सहारा  
अंगोला

बोत्सवाना

बरुण्डी

कैमेरून

केप वर्डी द्वीप समूह

केन्द्रीय अफ्रीका गणतंत्र

चाद

कमोरो द्वीप समूह

मंगो डाहिमें का गणतंत्र

भूमध्य गिनी (1)

इथोपिया

जाम्बिया

घाना

गिनी

ग्राइवरी कोस्ट

केनिया

सेसोथे

लाइबीरिया

मालागासी गणतंत्र

मालावी

माली

मारिनेमिया मारीशस

मुजाम्बीक

नाइगरा

पुर्तगाली गिनी

रियूनियन

रोडेथिया

रवांडा

सेन्ट हेलेना और डेम (2)

माफोटीम और प्रिंसाइज

सेनेगाल

सेजीसीज

सियरा लियोन

सोमालिया

सूडान

स्वाजी लैण्ड

टेरी प्रापन्स और इस्तास

टोगो

युगान्डा

तंजानिया संयुक्त गणतंत्र

अपर बोत्सा

जाइरे गणतंत्र

जाम्बिया

##### 3. दक्षिणीका उत्तरी और केन्द्रीय

बाह्रमस

बारबोडोस

बेलीज

बेरमुडा

कोस्टारिका

क्यूबा

डोमिनिकान गणतंत्र

एन साल्वेडोर

ग्वाटे लोप

ग्वाटे मासा

हेती

होण्डूरस

जमेका

मार्टिनिक  
मैक्सिको  
मीक्सिको एनटिलीज  
निकारगुवा  
पनामा  
सेन्ट पियरो और मिक्योलोन  
ट्रिनिडाड और टोबैगो

(1) पहले स्पेनी गिनी का प्रदेश, फरेन्डो पो द्वीप सहित

(2) निम्नलिखित द्वीपों सहित :-

अनेशन, ट्रिस्टन डा इन एक्मोसिबिलिस, नाइटिंगेल गफ

(3) मुख्य द्वीप समूह, भरव, बोनेरे क्युराकाओ, साहा, सेन्ट मार्टिन (दक्षिणी भाग)

वेस्ट इण्डोज (शाखा) एन आई ई

(क) सम्बन्धित राज्य (1)

(ख) आश्रित (2)

#### 4. दक्षिणी अमेरिका

अर्जेन्टीना  
बोलिविया  
ब्राजील  
चिली  
कोलम्बिया  
फोल्कलैंड द्वीप समूह  
फ्रांसीसी गिनी  
गुयाना  
पाराग्वे  
पीरू  
सूरिनाम  
ऊरुग्वे

#### 5. मध्य पूर्वी एशिया

बेहरीन  
ईजराइल  
जोर्डन  
लेबनान  
ओमान  
सिरियाई अरब गणतंत्र  
यूनाइटेड अरब एमीरात (3)  
यमन अरब गणतंत्र  
यमन जनवादी डी०आर० (4)

#### 6. दक्षिणी एशिया

अफगानिस्तान  
बांगला देश  
भूटान  
बर्मा  
भारत  
माल द्वीप  
नेपाल  
पाकिस्तान  
श्रीलंका

#### 7. सुदूर पूर्वी एशिया

ब्रुनी  
हॉंगकांग  
खमेर गणतंत्र  
कोरिया गणतंत्र  
लाओस

मकाओ  
मलेशिया  
फिलिपाइन  
सिंगापुर  
साइवान  
थाइलैण्ड  
तिमोर  
वियतनाम गणतंत्र  
वियतनाम जनवादी गणतंत्र

#### 8. ओसिनिया

कोक द्वीप समूह  
फिजी  
गिल्बर्ट और इलाइस द्वीप  
फ्रांसीसी पोलिनेशिया (5)  
नीरु  
न्यूक्लेडोनिया  
न्यू हेब्रीसिल हेसिसेस (आ० और के)  
नियु  
पोसिफिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य) (6)  
पापूवा न्यू गिनी  
सोलोमन द्वीप समूह (आ)  
टोंगा  
वालिस और फतुना  
पश्चिमी समाओ

#### 9. यूरोप

साइप्रस  
जिब्राल्टर  
ग्रीक  
माल्टा  
स्पेन  
सुर्की  
युगोस्लाविया

- (1) मुख्य द्वीप समूह :- एटिगुवा, डोमिनिका, ग्रेनाडा, सेन्ट किट्स (सेंट किट्सोफी), नेविस एन्गियुला, सेंट लूसिया और सेन्ट व्हेन्सेन्ट ।
- (2) मुख्य द्वीप मोन्तेसेरात, सेमान, तुर्कम और काइकोस और ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह ।
- (3) अजमान, बुबर्, फुआइरह, रास अल खेमाह, शारजाह और ऊम अल क्वैनेन ।
- (4) अवन और विभिन्न सुलतनत और असोसिएट सहित ।
- (5) सोसायटी द्वीप समूह (ताहिती सहित) को शामिल करते हुए फ्रांसीसी द्वीप समूह, दुआमोदु जाम्बीअर ग्रुप और माकेसस द्वीप समूह
- (6) वेसिफिक द्वीप समूह का ट्रस्ट प्रदेश, कारोलीन द्वीप समूह, मार्शल द्वीप समूह और मोरिना द्वीप समूह (गाम को छोड़कर)

(क-2) ओ० पी० ई सी० के सदस्य या सहयोगी देश

अल्जीरिया  
बोलिविया  
लिबिया अरब गणतंत्र  
गैबान  
नाइजीरिया  
इक्वेटोर

बेन्जुएला  
ईरान  
ईराक  
कुवैत  
कातार  
सऊदी अरब  
अबुधाबी  
इण्डोनेशिया

(3) ऐसे न्यायिक "व्यक्तियों" का पंजीकरण पात्र स्रोत देशों में होगा।

### 3.1. संविदा की कीमत

(क) संविदा कीमत जापान येन में दर्शाई जानी चाहिए, बशर्ते कि संविदा कीमत का वह भाग जो ठेकेदार अरबी के देशों में खर्च करेगा अरबी की मुद्रा में दर्शाया जाना चाहिए।

### (ख) मुख्य समंजन कंडिकाएं

बोली दस्तावेज में यह स्पष्ट विवरण होना चाहिए कि पक्की कीमतों में वृद्धि की आवश्यकता है अथवा बोली की कीमतों में वृद्धि स्वीकार्य है। यदि संविदा के प्रमुख लागत अवयवों आयात श्रम और महत्वपूर्ण सामग्री की कीमतों में कोई परिवर्तन होता तो संविदा की कीमतों में समंजन के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

कीमतों के समंजन के लिए विशिष्ट सूत्र बोली दस्तावेजों में माफ-साफ परिभाषित होना चाहिए। माल की सप्लाय के लिए संविदाओं में कीमतों के समंजन की उच्चतम निर्धारित सीमा को भी शामिल किया जाना चाहिए लेकिन सिविल कार्यों के लिए संविदाओं में इस प्रकार की उच्चतम निर्धारित सीमा को प्रायः शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

एक वर्ष के अन्दर सुपुर्व किए जाने वाले माल के लिए मुख्य समंजन की व्यवस्था प्रायः नहीं होनी चाहिए। ये मार्ग निर्देशन बिन्दु उन विभिन्न उपायों के परिचय का आभास नहीं कराती हैं जिनके द्वारा संविदा मुख्य समंजित किया जा सके।

### (ग) बीमा

मफल बोलीकार द्वारा दी जाने वाली बीमों की किस्तों का बोली दस्तावेजों में संक्षेप में वर्णन होना चाहिए।

3.2 दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित संविदा या विदेशों संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आदेश से समर्थित क्रय आदेश जो भारतीय आयातक द्वारा विदेशी संभरक को दिया गया है, या इनकी फोटो प्रतियां भी कण्ड को स्वीकार्य है।

3.3 प्रत्येक संविदा में संभरक की पात्रता का निम्नलिखित विवरण जोड़ा जाएगा :-

"मैं (हम) एबद्धाया यह उल्लेख करते हैं कि मेरी (हमारी) कम्पनी पात्र संभरक है क्योंकि शेयरों का ----- प्रतिशत (%) ----- (पात्र स्रोत देश) के राष्ट्रियों द्वारा रखा गया है, और ----- प्रतिशत ( ) निदेशक ----- (पात्र स्रोत देश) के राष्ट्रिक है और मेरी (हमारी) कम्पनी ----- (पात्र स्रोत देश) में पंजीकृत कराई गई है।

### 4.1. मानदण्ड

यदि उन राष्ट्रीय मानदण्डों का उल्लेख किया जाता है जिनके अनुसार ही उपकरण या माल है तो विशिष्टिकरण में यह दर्शाया जाना चाहिए कि जापान औद्योगिक मानदण्ड या अन्य स्वीकार किए गए अन्तराष्ट्रीय मानदण्ड को पूरा करने वाली पण्यवस्तुएं जो मानदण्डों की कोटि के बराबर या इससे अधिक मानदण्ड का सुनिश्चय करती हैं उन्हें भी स्वीकार कर लिया जाएगा।

### 4.2. कण्ड नामों का प्रयोग

यदि विशेष प्रकार के फालतु पुर्जों की आवश्यकता है या यह निश्चय किया गया है कि कुछ खास आवश्यक विशेषताओं को बनाए रखने के लिए मानकीकरण की एक डिग्री की आवश्यकता है तो विशिष्टिकरण निष्पादन क्षमता पर आधारित होने चाहिए और उन्हें एक केवल कण्ड नाम, सूची सख्या और विशेष विनिर्माता के उत्पादों को निर्धारित करना चाहिए।

### अनुबन्ध-2

प्रो० ई० सी० एफ० द्वारा व्यवस्थित परियोजना अर्ण के अधीन माल और सेवाएं अधिप्राप्ति करने के लिए मुख्य मार्ग दर्शन

### 1. विभाजन

आपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के अधीन सभी संविदाएं बोली आमंत्रित करने के लिए अरबी देश में सामान्य प्रकार के लिए कम से कम एक समाचार पत्र में विज्ञापित होनी चाहिए।

### 2. बोली के दस्तावेज और संविदाएं

#### 2.1. बोली बाण्ड और गारंटियां

बोली बाण्ड या बोली की गारंटियां साधारण आवश्यकताएं हैं, लेकिन इनको इतना कठिन नहीं बनाना चाहिए जिससे कि उचित बोलीकार हतोत्साहित हो जाए। बोली खुलने के पश्चात जैसे ही संभव हो बोली बाण्ड भ्रमसा गारंटियां अमफल बोलीकारों को रिहा कर देनी चाहिए।

#### 2.2. संविदा की शर्तें :

2.2 संविदा के प्रशासन और उसके अधीन किए गए किन्हीं परिवर्तनों में भी गई संविदा की शर्तों में आयातक और ठेकेदार या संभरक के अधिकार और दायित्व और आयातक द्वारा कोई इंजीनियर नियुक्त किया गया है तो उसके अधिकार और प्राधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए। संविदा की परम्परागत सामान्य शर्तें, जिनमें से कुछ का उल्लेख इन निर्देशन बिन्दुओं में किया गया है, के प्रतिरिक्त परियोजना के स्वरूप और स्थिति के लिए उपयुक्त विशेष शर्तों को भी शामिल करना चाहिए।

#### 2.3. संविदाओं की किस्म और प्रकार

संविदाएं निष्पादित काम के लिए इकाई मूल्य के या आनेदित मर्चों के या एक मुख्य कीमत के या संविदा के विभिन्न भागों के लिए दोनों के समन्वय के आधार पर, प्रदान किए जाने वाले माल या सेवाओं के स्वरूप के अनुसार की जा सकती हैं और बोली लगाने वाले दस्तावेजों में जुमी गई संविदा की किस्म की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। वास्तविक मूल्य की प्रतिपूर्ति पर मुख्यतः आधारित संविदाएं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर निधि को स्वीकार्य नहीं हैं। इंजिनियरिंग उपकरण और निर्माण के लिए उसी पार्टी द्वारा प्रदान की जाने वाली एकल संविदाएं (टैन्की संविदाएं) यदि अरबी देश के लिए तकनीकी और आर्थिक लाभ प्रदान करें तो वे स्वीकार्य हैं।

#### 2.4. पात्र संभरक

वे नियतक या संभरक जिनके माल एवं सेवाओं का वित्तदान अर्ण की रकम में से किया जाना है (जिसे इसके बाद "पात्र संभरक" कहा गया है), पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक होंगे और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेंगे:-

- (1) अधिदान किए गए शेयरों का एक बड़ा भाग पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा रखा जाएगा।
- (2) पूर्णकालिक निदेशकों बहुमत पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों का होगा।

बाद वाले मामले में विनिश्चयन को उन विकल्पों पर प्रस्तावों के प्रस्तावों की अनुमति देनी चाहिए। जिनकी विशेषता मिलती जुलती हैं और कम से कम उन विनिश्चयन के बराबर विचारण और गुण उत्तम हैं।

#### 4. 3. गारंटी, निष्पादन बांड और रोकी गई धनराशि

नागरिक कार्य के लिए बोली दस्तावेज में गारंटी के लिए कुछ जमानत के रूप में होना चाहिए जिससे कि जब तक यह पूरा न हो जाए सब तक काम जारी रहेंगे। यह जमानत या तो बैंक गारंटी द्वारा अथवा निष्पादन बांड द्वारा दी जा सकती है, इसकी धनराशि कार्य की किस्म और परिमाण के अनुसार भिन्न-2 होगी, लेकिन ठेकेदार में कभी पाए जाने के मामले में श्रमों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। उचित जमानती अवधि को पूरा करने के लिए संविदा को पूर्ण होने के बाद भी इसमें पर्याप्त रूप से समय में वृद्धि की जानी चाहिए। गारंटी या अपेक्षित बांड की धनराशि को बोली दस्तावेजों में निरूपित किया जाना चाहिए।

भाल की सप्लाई के लिए संविदाओं में आम तौर पर यह वांछनीय होगा कि बैंक गारंटी अथवा बांड की अपेक्षा गारंटी निष्पादन के लिए रोक रखी गई धनराशि के ही कुल भुगतान का प्रतिशत माना जाए। रोकी रखी गई धनराशि को कुल भुगतान की दर मानना और हमके अस्तित्व भुगतान के लिए शर्तें बोली दस्तावेज में निविष्ट होनी चाहिए। लेकिन, यदि बैंक गारंटी अथवा बांड चुना जाता है तो यह केवल नाम मात्र धनराशि के लिए ही होना चाहिए।

#### 5. चुकाई जाने वाली क्षति

श्रमों को जब कार्य पूर्ण होने या सुपुर्दी में ढेर होने के कारण फालतू खर्चा, राजस्व की हानि या अन्य लाभों में नुकसान होता है तो बोली दस्तावेजों में चुकाई जाने वाली क्षति से सम्बद्ध प्रावधान शामिल होने चाहिए। ठेकेदार द्वारा संविदा में निविष्ट समय पर अथवा उससे पहले नागरिक निर्माण कार्य पूरा करने के लिए और जब कि समय से पूर्व पूर्ण किया गया कार्य श्रमों को लाभकारी हो तो ठेकेदार का बोनस देने की भी व्यवस्था की जाए।

#### 6. बाध्यकारी परिस्थिति

बोली दस्तावेजों में शामिल की गई संविदा की शर्तों में जब उचित हो तो इसे अनुबंधित करते हुए इस सम्बन्ध में वाक्यांश होने चाहिए कि संविदा के अन्तर्गत पार्टी द्वारा अपने अधिकारों को न पूरा करना उन हालात में एक चूक नहीं माना जाएगा यदि ऐसी चूक विषय स्थितियों में (फॉर्स मेज्योर) के फलस्वरूप हुई है। (संविदा की शर्तों में इसकी परिभाषा की जानी है)।

#### 7. झगड़ों का निपटारा

झगड़ों के निपटारा से सम्बन्धित व्यवस्थाएं संविदा की शर्तों में शामिल की जानी चाहिए। यह वांछनीय है कि व्यवस्थाएं अन्तरराष्ट्रीय वाणिज्य मंडल द्वारा बनाए गए "समझौते और मध्यस्थ निर्णय के नियमों" पर या अन्य ऐसी व्यवस्थाएं जो भारतीय प्रायातक और विदेशी संभरक दोनों को स्वीकार्य हो, पर आधारित होनी चाहिए।

#### 8. भाषा की व्याख्या

बोली दस्तावेज अंग्रेजी में तैयार किए जाने चाहिए। यदि बोली दस्तावेजों में अन्य भाषा इस्तेमाल में लायी जाए तो ऐसे दस्तावेजों के साथ अंग्रेजी भी होनी चाहिए और इस बात का भी उल्लेख किया जाए कि कौन सी भाषा प्रमुख है।

#### 9. बोली खोलना, मूल्यांकन और ठेका देना

##### 9. 1. बोलियों के आमंत्रण और बोली प्रस्तुत करने के बीच का समय

बोली तैयार करने के लिए अनुमत समय अधिकतर संविदा की महत्वता और पेशीवगी पर निर्भर करेगा। साधारणतः अन्तरराष्ट्रीय बोली

के लिए कम से कम 45 दिनों की स्थिति हो जानी चाहिए। जहाँ पर नागरिक निर्माण कार्य अधिक है, वहाँ पर प्रत्याशित बोलीकारों को अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने में पर्याप्त और भली-भांति वेक-माथ केने के लिए आम तौर पर कम से कम 90 दिन दिए जाने चाहिए। किन्तु अनुमत समय प्रत्येक परिस्थिति से सम्बन्धित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए।

##### 9. 2. बोली खोलने की क्रियाविधि

बोलियों को अन्तिम पात्रों के लिए और बोली लगाने के लिए निविदा समय और स्थान को बोली आमंत्रण में घोषित किया जाना चाहिए और सभी बोलियों निर्धारित समय पर खुले आम खोलनी चाहिए। इस समय के बाद प्राप्त हुई बोलियों को बिना खोले ही लौटा देना चाहिए यदि उन्होंने अनुरोध किया है या उन्हें अनुमति दे दी गई है तो बोलीकार का नाम और प्रत्येक बोली का और किसी वैकल्पिक बोलियों की कुल धनराशि जोर से पढ़ी जानी चाहिए और उचित रिहाई कर लेना चाहिए।

##### 9. 3. बोलियों का स्पष्टीकरण या उत्तरों परिवर्तन

बोली खोलने के पश्चात् किसी भी बोली खोलने वाले को उसकी बोली में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। केवल स्पष्टीकरणों को ही स्वीकार किया जाए जिससे बोली के मूल सत्य पर कोई प्रभाव न पड़े। आमतौर पर किसी भी बोली खोलने वाले से अपनी बोली के विषय में स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है लेकिन बोलीकार को उसकी बोली के सारांश एवं मूल परिवर्तन के विषय में नहीं कहना चाहिए।

##### 9. 4. गुप्त रखी जाने वाली क्रियाविधि

कानून द्वारा यथा अपेक्षित को छोड़कर बोली खोलने के बाद बोली से संबंधित निरीक्षण, स्पष्टीकरण एवं मूल्यांकन और निर्णय से सम्बन्धित निगरानियों के बारे में भी उन शर्तों को जो हों क्रियाविधियों से औपचारिक रूप से सम्बन्धित नहीं है तब तक नहीं बताया जाना चाहिए जब तक कि सफल बोलीकार के लिए संविदा के निर्णय को घोषित नहीं कर दिया जाता है।

##### 9. 5. बोलियों की जीत

बोलियों के खोलने के बाद हुता सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि क्या कोई बोलियों के परिवर्तन में विषय सम्बन्धी गन्ती तो नहीं लिख दी गई है, क्या बोली दस्तावेज विरुद्ध बोलियों के अनुसार है, क्या आवश्यक जमानतों को वापस कर दी गई है, क्या दस्तावेज विधिवत हस्ताक्षरित हैं और क्या बोलियों सामान्यतया अन्यथा रूप से सही हैं, यदि बोलियाँ मूल रूप से विनिश्चयन के अनुसार नहीं हैं या उसमें अस्वीकृत शर्तें हैं या अन्यथा रूप से बोली सम्बन्धी दस्तावेजों के अनुसार नहीं हैं तो उन्हें अस्वीकृत किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक बोली के मूल्यांकन के लिए और बोलियों के मिलाप के लिए तत्समोक्ति विवेचन किया जाना चाहिए।

##### 9. 6. बोलीकार की पूर्व योग्यताएं

पूर्व योग्यताओं की अनुपस्थिति में प्रायातक को चाहिए कि वह इस बात का सुनिश्चय करे कि उस बोलीकार के पास सम्बन्ध संविदा को प्रभावी रूप से चलाने के लिए क्षमता है और धन है जिसकी बोली का कम से कम मूल्यांकन किया गया है। यदि बोलीकार उस योग्यताओं को पूरा नहीं करता तो उसकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

##### 9. 7. बोलियों का मूल्यांकन और मिलाप

बोलियों का मूल्यांकन बोली दस्तावेजों में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार होना चाहिए। गणितीय शक्तियों के लिए समंजित बोली को कीमत के अनिवार्य अन्य बातों जैसे निर्माण कार्य के पूर्ण होने का



समय, उपकरण की कार्य कुशलता एवं क्षमता या कालतु पुर्णों की उप-सम्पत्त और प्रस्तावित निर्माण कार्य तरीकों की विश्वसनीयता को विचार में लिया जाना चाहिए। जहाँ तक सम्भव हो वे बातें बोली दस्तावेजों में विशिष्टीकृत मानदण्ड के अनुसार बताने की शर्तों में सम्मिलित की जानी चाहिए यदि कोई हो तो बोली में शामिल की गई सम्पत्ति की कीमत के लिए वृद्धि की धनराशि विचार में नहीं ली जानी चाहिए।

प्रत्येक बोली में मुद्रा अथवा मुद्राएँ जिनमें मूल्य प्रांका जाता है बोली स्वीकृत होने पर श्रुति द्वारा भुगतान किया जाएगा और सभी बोलियों की तुलना श्रुति द्वारा चुनी गई एक ही मुद्रा में मूल्यांकित होनी चाहिए और इसका उल्लेख बोली दस्तावेजों में भी होना चाहिए। ऐसे मूल्यांकन में उपयोग के लिए दिनगण की दर सरकारी स्रोत द्वारा प्रकाशित विक्रय दरों पर होनी चाहिए और जब तक निर्णय होने से पूर्व मुद्रा के मूल्य में कोई परिवर्तन न किया जाए तब तक बोलियाँ खोलने के दिन उसी प्रकार के भुगतानों पर लागू होनी चाहिए। ऐसे मामलों में सफल बोलीकार के निर्णय को अधिसूचित करते समय विनियम की दर उपयोग में लाई जानी चाहिए।

#### 9.8. बोलियों को प्रस्वीकृत करना

बोली दस्तावेजों में सामान्यता यह व्यवस्था की गई है कि श्रुति सभी बोलियों को प्रस्वीकृत कर सकते हैं। लेकिन बोलियों को प्रस्वीकार नहीं करना चाहिए और नई बोलियों में कम कीमत प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ उसी विशिष्टीकरण पर नई बोलियाँ प्रामाणित नहीं की जानी चाहिए। यह उन मामलों को छोड़कर होगा जहाँ न्यूनतम मूल्यांकित बोली वास्तविक धनराशि द्वारा अनुमानित कीमत से अधिक हो जाती है। सभी बोलियों को प्रस्वीकार करने के लिए भी तब अधिसूचित करने चाहिए जहाँ (क) बोलियाँ, बोली दस्तावेज के भाग्य के अनुसार न हो या (ख) बहुत कम प्रतियोगिता है। यदि सभी बोलियों को प्रस्वीकार कर दिया जाता है तो श्रुति को चाहिए कि वह उस कारण या उन कारणों की पुनरीक्षा करे जिससे प्रस्वीकृति सिद्ध की गई है और या तो विशिष्टीकरण के परिवर्तनों पर या परियोजना के परिशोधन पर (या बोलियों के लिए मूल प्रामाणन में मांगी गई पण्य वस्तुओं की धनराशि पर) या दोनों पर विचार करें। विशेष परिस्थितियों में निधि पर विचार करने के बाद श्रुति संतोषजनक संविदा प्राप्त करने के लिए किसी एक कम से कम बोली देन वाले बोलीकार या दो बोलीकारों के साथ सौदा कर सकता है।

#### 9.9. संविदा का निर्णय

संविदा का निर्णय उस बोलीकार के लिए किया जाना चाहिए जिसकी बोली न्यूनतम मूल्यांकित बोली पर निश्चित की गई है और जो क्षमता और वित्तीय साधनों के उचित मानक को पूरा करता है। ऐसे बोलीकार के लिए यह आवश्यक नहीं होना चाहिए कि वह निर्णय को एक शर्त के रूप में विशिष्टीकरण में निर्धारित पण्यवस्तुओं के लिए या अपनी बोली को परिशोधित करने के लिए जिम्मेवारी ले।

#### अनुबन्ध 3

##### प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र

सं०..... दिनांक.....

सेवा में,

सहायता, लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,

वित्त मंत्रालय,

प्राथमिक कार्य विभाग,

यू० सी० ब्रो० बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल,

फालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

विषय:-येन क्रेडिट सं० आई० डी० पी० -14 (परियोजना सहायता)

के अधीन जापान से ..... का आयात।

1239 GI/81-2

सहोदय,

ऊपर उल्लिखित येन क्रेडिट आई० डी० पी० 14 (परियोजना सहायता) के अधीन ..... से ..... जो कि ..... के आयात के सम्बन्ध में ..... (बैंक का नाम) जो कि बही होना चाहिए जो नीचे (क) में सम्बद्ध समुद्रपार संभरक के नाम में साखपत्र खोलने के लिए दिया गया है को प्राधिकारपत्र जारी करने के लिए हम आपको निम्नलिखित स्वीरे प्रस्तुत करते हैं :-

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता

(ख) आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य और वह तरीका जिस तक वैध है।

(ग) प्राप्ति के तरीके----- क्या वह सीधे क्रय या औपचारिक खुले अंतर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है। इसके मामले में यदि कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेतित होना चाहिए कि क्या संविदा का निर्णय उपयुक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।

(घ) माल का संक्षिप्त विवरण

(ङ) माल का उद्गम देश

(च) यदि कोई हो तो पात्र से हतर स्रोत देशों से आयातित संघटकों का प्रतिशत।

(छ) संविदा का कुल जहाज पर निःशुल्क मूल्य (येन में)

(ज) यदि कोई हो तो भारतीय एजेंट के कमोशन की धनराशि (येन में)

(झ) वास्तविक जहाज पर निःशुल्क मूल्य (येन में) जिसके लिए प्राधिकार पत्र मांगा गया है।

(ञ) समुद्रपार के संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या एवं दिनांक

(ट) समुद्रपार के संभरक का नाम और पता :-

(1) राष्ट्रियता

(2) पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रियों द्वारा लिए गए श्रेयों का प्रतिशत

(3) प्रतिनिधि की राष्ट्रियता और/या संभरक का निवास स्थान

(4) उन निदेशकों का प्रतिशत जो पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक हैं

(ठ) वे भुगतान शर्तें और सम्भावित तिथि जिनको संविदा के अन्तर्गत भुगतान देय होंगे।

(ड) सुपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि।

(ड) भारतीय बैंक टीकियों को भुगतान करते समय किए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और उनका निपटान दिखाते हुए)

(ण) पोतलदान अनुदेश वाहानास्तरण पार्टशिपमेंट की अनुमति दी गई है या नहीं निविष्ट कीजिए।

(त) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता।

(थ) क्या उसी लाइसेंस के अन्तर्गत संविदा (संविदाएं) कर दी गई हैं और जापानी प्राधिकारियों को अधिसूचित कर दी गई है। यदि तो ऐसी प्रत्येक संविदा का नाम, दिनांक और मूल्य और वित्त मंत्रालय का वह संदर्भ जिसके अन्तर्गत आई० डी० सी० एफ० को इसे अधिसूचित किया गया है।

अनुबन्ध 4

(प्राधिकार पत्र का प्रपत्र)

संख्या एक

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक:

सेवा में,

बैंक आफ इंडिया,  
टोकियो शाखा,  
टोकियो, (जापान)

विषय:—येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) ऋण करार सं० आई०डी०पी० 14 के अधीन आयात साख पत्र खोलने के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना।

प्रिय सहोदय,

आपके बैंक के साथ 25-3-1980 को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एनबद्वारा यथा संलग्न ग्योरे के अनुसार सर्वश्री ..... के नाम में ..... येन धनराशि के लिए अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

आपके बैंक द्वारा खोले गए प्रत्येक साखपत्र की प्रति आयातक के बैंक ओ० ई० सी० एफ० भारतीय दूतावास टोकियो और हमें पृष्ठांकित की जाए।

साखपत्र की शर्तों के अनुसार प्रारंभ में संभरकों को भुगतान आपकी तिथि से किया जाएगा। भुगतान के बाद ओ० ई० सी० एफ० को आवश्यक दस्तावेज भेज कर किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति का दावा तत्काल करना चाहिए।

संभरक को आपके द्वारा किए गए भुगतान की तिथि से और ओ० ई० सी० एफ० द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति की तिथि के बीच के समय के लिये उपर्युक्त समझौते के अनुसार भारतीय दूतावास टोकियो द्वारा सीधे ही ब्याज दिया जायेगा और उसका निर्धारण आपके द्वारा भारत में संबंधित आयातक बैंक के साथ सामान्य बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किये बिना किया जायेगा। बैंकों के अन्य खर्च जिसमें साखपत्र खोलने, रख-रखाव करने और साखपत्रों को जारी रखने के लिये खर्च भी शामिल हैं क्योंकि वे भी परक्राम्य दस्तावेजों के संचालन से संबंधित हैं और यदि कोई हो तो, विदेशी संभरकों के बैंकों के खर्च भी विदेशी संभरक को ही देने पड़ेंगे और इसलिये आयातक द्वारा उनका भुगतान नहीं किया जायेगा और इसलिये उन्हें सीधे ही संभरका से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार ऐसे भुगतानों की प्रतिपूर्ति का दावा ओ० ई० सी० एफ० में नहीं किया जा सकता। जब ओ० जीसे ही आपके द्वारा कोई भुगतान किया जाता है और आपको प्रतिपूर्ति की जाती है वो निर्धारित प्रपत्र में एक सूचना इस मंत्रालय को भेजनी चाहिये।

यह प्राधिकारपत्र समुहवार संभरकों के नाम में साखपत्र खोलने के लिए है। इस मंत्रालय के विशिष्ट प्राधिकार के बिना इस प्राधिकरण के मई खोले गए आगे के नए साख-पत्र या साखपत्र के बाद के संशोधनों का अनुपालन नहीं किया जाएगा।

यह प्राधिकारपत्र ..... तक वैध रहेगा।

भवदीय,

लेखा अधिकारी

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. आयातक ..... का उनके पत्र सं० ..... दिनांक ..... के संदर्भ में।

2. आयातक के बैंक ..... उनसे निवेदन किया जाता है कि बैंक आफ इंडिया टोकियो शाखा से वस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरक को येन के बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करें। संभरकों को चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपए की गणना सार्वजनिक सूचना सं० 8-आईटीसी (पी एन)/76, दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी ही सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए के अनुसार संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी। विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि से भारतीय बैंक को अदायगी करने की तिथि से सरकार के लेखे में तुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना सं० 46-आईटीसी (पी एन)/76, दिनांक 16-6-76 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक दर पर और उससे अधिक की गणना की गई अवधि के लिए 15 प्रतिशत की दर से ब्याज भी सरकारी लेखे में जमा कराना होगा। ब्याज दोनों दिनों के लिए दिया जाएगा अर्थात् वह तिथि जिसको विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और वह तिथि जो जिसको सरकारी लेखे में जमा रुपए निक्षेप किया जाता है। यदि इस दर में कोई परिवर्तन किया गया तो तुरन्त इसकी सूचना दी जाएगी। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमाशुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल सेट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जानी है।

ये धनराशियां या तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में जमा करनी चाहिए। इस संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं० 184-आईटीसी (पी एन)/68, दिनांक 30-8-68, सं० 233 आईटीसी (पी एन)/68, दिनांक 24-10-68, सं० 132-आईटीसी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71, सं० 74-आईटीसी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-74 और सं० 103-आईटीसी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-1976 को शर्तों की ओर दिलाया जाता है। लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह "के—डिपोजिट्स एंड एडवांसिज 843—सिवल डिपोजिट्स—डिपोजिट्स फार परचेजिज एक्सेक्यूट एमाड परचेजिज अंडर क्रेडिट/लोन एग्रीमेंट-7.6 बिलियन येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं० आईटीपी-14 फार 1981-82 फीम दी गवर्नमेंट आफ जापान" है।

जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना सं० 132-आईटीसी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71 के अनुसार नकद जमा किया जाता है, उनको ब्याज की मूल रूप में एक प्रतिनिधि बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अवशेष पत्र सहित निम्नलिखित पते पर भेजनी चाहिए :-

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,  
वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग),  
पहली मंजिल यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग,  
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

जिन मामलों में तुल्य रुपया ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना सं० दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित वर्शनी हुण्डो द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में, जमा किए गए तुल्य रुपए का पूरा ब्योरा इस विभाग को भेजना चाहिए।

संभरकों को किए गए भुगतान की तिथि से बैंक आफ इंडिया, टोकियो को उसकी प्रतिपूर्ति की तिथि तक आईटीसीएफ द्वारा बैंक आफ इंडिया, टोकियो को किए गए ब्याज प्रभार बैंक आफ इंडिया, टोकियो के साथ सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से भारत सरकार के लेखे को प्रभावित बिना सीधे ही आपके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

3. निदेशक, श्रृण विभाग-2, समुद्र-मार आर्थिक सहयोग निधि, टेक्नो-म्यूट्रिबलिंग, 4-1 ओहा, मेची-1-कोमे, चियोडा-कु, टोकियो-100, जापान।

4. भारतीय रूपावास, टोकियो।

5. अवर सचिव, जापान अनुभाग, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।

लेखा अधिकारी

अनुबंध 5

(सी० ई० सी० एफ० एल० सी०-1 का प्रपत्र)

अपरिवर्तनीय साख-पत्र

(माल के लिए लागू)

सेवा में, दिनांक .....

..... यह साख-पत्र (ऋणी) और विदेशी  
..... आर्थिक सहयोग निधि के बीच  
(संभरक का नाम और पता) हुए ऋण करार सं० .....  
..... के दिनांक .....  
के अनुसरण में जारी किया गया है।

प्रिय महोदय,

हम सूचित करते हैं कि हमारे नाम में निकालने के लिए बीजक के पूरे मूल्य के लिए दशमि हुण्डी द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए हमने अपरिवर्तनीय साख-पत्र सं० ..... खोल दिया है जो ..... येन (..... येन कह सकते हैं) की कुल धनराशि से अधिक नहीं है, इसे निम्नलिखित दस्तावेज के साथ भेजा जाना है :-

हस्ताक्षरित, वाणिज्यिक बीजक

कलीन धान बीज, समुद्री पीत लवण बिल जिनमें दिए गए भादेशों का पूरा सेट हो बैंक पृष्ठांकित एवं चिह्नित "फ्रेड" एवं "नोटिफाई"

अन्य दस्तावेज जिसमें ..... से ..... तक लवण का उत्पादन किया गया हो संविदा संख्या ..... (यदि कोई हो) के संदर्भ में संक्षिप्त विवरण आंशिक पोतलवान स्वीकृत है। बाह्योत्पन्न स्वीकृत है।

पोतलवान बिल जो ..... से प्राप्त की तिथि का नहीं होना चाहिए। भादेशों को ड्राफ्ट ..... 19 तक अवश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

इस क्रेडिट के अंतर्गत सभी ड्राफ्ट और दस्तावेजों पर यह अंकन होना चाहिए। "अपरिवर्तनीय साख-पत्र सं० ..... दिनांक ..... 19 के अंतर्गत निकलवाया गया और आयात संदर्भ संख्या (संख्याएं) यदि कोई हों, यह क्रेडिट हस्तांतरणीय नहीं है।"

हम एतद्वारा वचन देते हैं कि इस क्रेडिट के अंतर्गत और इसकी शर्तों का अनुपालन करते निकलवाए गए सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर और भादेशों को दस्तावेजों की सुपुर्गों पर विधिकृत स्वीकार किए जाएंगे।

जब तक अग्र्यथा रूप से विस्तारपूर्वक न बताया जाए कि क्रेडिट "यूनिफार्म कस्टम एंड प्रेक्टिस फार ड्राफ्ट्स (1974 रिवीजन) इंटर-नेशनल बैंक ऑफ कामर्स, पब्लिकेशन सं० 290" के अधीन है। सौदा करने वाले बैंक के लिए विशेष अनुदेश :-

1. उपर्युक्त ऋण करार के अंतर्गत जारी किए गए वचनपत्र की व्यवस्थाओं के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि द्वारा हमारे भुगतान के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम वचन देते हैं कि हम सौदा करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार हुण्डों की धनराशि को लौटा देंगे।

2. सौदा करने वाले बैंक को यह बताते हुए हमें ड्राफ्ट्स और दस्तावेजों का एक पूर्ण सेट और इसके साथ एक प्रमाणपत्र अवश्य भेजें कि शेष दस्तावेज सीधे ही हवाई डाक द्वारा ..... को भेज दिए गए हैं।

3. इस क्रेडिट के अंतर्गत सभी बैंक के खर्चे आयातक संभरक के लेख के लिए हैं।

महोदय,

(.....)

वाणिज्य बैंक

द्वारा .....

प्राधिकृत हस्ताक्षर

भुगतान शर्तें

यह भुगतान हमारे साख-पत्र सं० ..... का अभिन्न अंग है।

1. प्रारंभिक भुगतान

धनराशि ..... येन जो कि कुल संविदा मूल्य के ..... प्रतिशत है।

अपेक्षित दस्तावेज

प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

2. मध्यवर्ती भुगतान (यदि कोई हो)

धनराशि ..... येन

जो कि कुल संविदा मूल्य का ..... प्रतिशत है।

अपेक्षित दस्तावेज

प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

3. पोतलवान दस्तावेजों के मद्दे भुगतान

धनराशि ..... येन

संविदा के कुल मूल्य का ..... प्रतिशत है।

टिप्पणी :- पोतलवान दस्तावेजों के मद्दे पूर्ण भुगतान के मामले में इस संलग्न दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है।

अनुबंध 6

(प्रपत्र सी० ई० सी० एफ० एल० सी० 2)

अपरिवर्तनीय साख-पत्र

(सेवाओं के लिए)

सेवा में,

दिनांक .....

..... यह साख-पत्र ऋणी और विदेशी  
..... आर्थिक सहयोग निधि के बीच हुए  
..... ऋण करार सं० .....  
(संभरक का नाम व पता) दिनांक ..... के अनुसरण में  
जारी किया गया है।

प्रिय महोदय,

हम आपको सूचित करते हैं कि हमारे नाम में निकालने के लिए पूर्ण और मूल्य के लिए लाभकारी ड्राफ्ट एंड साइट द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए आपके नाम में हमने अपरिवर्तनीय साखपत्र सं० ..... खोल दिया है जो ये ..... (येन ..... पहले) की कुल धनराशि से अधिक नहीं है।

इसमें संलग्न भुगतान अनुसूची के अनुसार अपेक्षित (संविदा ..... और परियोजना ..... ) से संबंधित वस्तावेजों को नवी करनी है सोदा तय करने के लिए ड्राफ्ट ..... से पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

सभी ड्राफ्ट और वस्तावेज अपरिवर्तनीय साखपत्र सं० ..... वित्तोंक ..... के अंतर्गत भुना लिए गए हैं से विहित होने चाहिए।

यह क्रेडिट हस्तांतरणीय नहीं है।

हम एतद्वारा वचन देते हैं कि इस क्रेडिट के अंतर्गत इसकी शर्तों का अनुपालन करके भुनाए गए सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर और भादेशिती को वस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत स्वीकार किए जाएंगे।

जब तक अन्यथा रूप से विस्तारपूर्वक न बताया जाए यह क्रेडिट "यूनिफार्म कस्टम एंड प्रेक्टिस फार ड्राफ्ट्स (1974 रिबीजन) इंटरनेशनल बैंक ऑफ कामर्स, नं० 290" के अधीन है।

सोदा करने वाले बैंक को विशेष अनुदेशः

इसमें संलग्न प्रपत्र के अनुसार (ऋणी और इसके मनोनीत प्राधिकारी) द्वारा जारी किए गए निष्पादन के मूल वितरण की प्राप्ति के पश्चात् इस क्रेडिट के अंतर्गत भुगतान इसमें संलग्न शीट में निर्धारित भुगतान अनुसूची के अनुसार किए जाने चाहिए। प्रारंभिक भुगतान के मामले में उपर्युक्त निष्पादन के विवरण में अज्ञात लाभकारी विवरण की आवश्यकता है।

2. ऊपर उल्लिखित ऋण समझौते के अधीन जारी किए गए वचनबद्धता पत्र के उपबंधों के अनुसार विदेशी प्राधिक सहयोग निधि से अपने भुगतानों के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम ड्राफ्टों की धनराशि का मोल-मोल करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार परेषित करने का वचन देते हैं।

3. उपर्युक्त मब 1 में यथा उल्लिखित वस्तावेज की एक प्रति और मसौदे हमें उसकी प्राप्ति के तुरन्त बाद ही भेजे जाएंगे।

4. इस साख के अंतर्गत बैंक के सभी खर्च आयातक संभरकों को लेखे के लिए हैं।

भवदीय,

(वाणिज्यिक बैंक)

द्वारा .....

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

भुगतान अनुसूची

यह भुगतान अनुसूची हमारे साखपत्र सं० ..... का एक अभिन्न अंग है।

1. प्रारंभिक भुगतान

धनराशि ..... येन

कुल संविदा मूल्य का ..... प्रतिशत है।

अपेक्षित वस्तावेज लाभकारी विवरण की अंतिम भुगतान तिथिः

2. भुगतान वृद्धि

संपूर्ण योग की धनराशि ..... येन

कुल संविदा मूल्य का ..... प्रतिशत

निम्न प्रकार से भुगतान किया जाना है:—

येन धनराशि ..... अंतिम भुगतान तिथि

येन .....

पहली किस्त ..... येन .....

दूसरी किस्त ..... येन .....

.....

अपेक्षित वस्तावेज (ऋणी अथवा उसके मनोनीत प्राधिकारी) द्वारा जारी किए गए निष्पादन के विवरण की एक प्रति जिसका एक प्रपत्र संलग्न है।

निष्पादन का विवरण

वित्तोंक .....

संवर्ध सं० .....

सेवा में, .....

(संभरक का नाम और पता)

संवर्धः—ऋण करार सं० ..... के अंतर्गत ..... परियोजना से संबंधित ..... के नाम में ..... येन के लिए ..... द्वारा जारी किए गए साखपत्र की सं० ..... वित्तोंक ..... में, अधोहस्ताक्षरी, प्रतिनिधि (ऋणी) एतद् द्वारा ..... और ..... के बीच समझौता सं० ..... वित्तोंक ..... में निहित भुगतान की शर्तों के अनुसार समुद्रवार प्राधिक सहायता निधि द्वारा ..... की धनराशि ( ..... येन केवल) प्राप्त करने के लिए एक निष्पादन विवरण जारी करता हूँ।

( ..... )

(ऋणी)

द्वारा .....

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

विशेष अनुदेशः—

वास्तविक निष्पादन का विवरण इसमें संलग्न पत्र में दर्शाया जाएगा।

मणि नारायणस्वामी,

मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 5-ITC(PN)82

New Delhi, the 23rd January, 1982

Subject : Licensing conditions in respect of import of goods and services under the Yen Credit of Yen 7.6 Billion for the implementation of the Lower Metter Hydro Electric Project of the Tamil Nadu State Electricity Board extended by the Overseas Economic Co-operation Fund (OECF) of Japan.

**F. No. IPC/23/(24)/81.**—The terms and conditions governing the issuance of import licence in respect of import of goods and services under the OECF Loan Agreement No. ID-P 14 of Yen 7.6 Billion for implementation of the Lower Mettur Hydro Electric Project of the Tamil Nadu State Electricity Board, as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

Appendix to Ministry of Commerce Public Notice No. 5-ITC(PN)/81 dated the 23rd January, 1982

**LICENSING CONDITIONS IN RESPECT OF IMPORTS OF GOODS AND SERVICES UNDER THE YEN CREDIT OF YEN 7.6 BILLION FOR THE IMPLEMENTATION OF THE LOWER METTUR HYDRO ELECTRIC PROJECT OF THE TAMIL NADU STATE ELECTRICITY BOARD EXTENDED BY THE OVERSEAS ECONOMIC CO-OPERATION FUND (OECF) OF JAPAN :**

#### Section I—General conditions :

I(i) The Yen Credit of Y 7.6 billion extended by the Overseas Economic Co-operation Fund of Japan (OECF) for financing the import requirements of the Lower Mettur Hydro Electric Project of the Tamil Nadu State Electricity Board (TNSEB) is untied in favour of developing countries. Accordingly the goods and Services to be procured under this credit can be imported from Japan and all countries enumerated in the list at Annexure-I which will be eligible source countries under the credit.

I(ii) Import Licence(s) under the Credit can be issued only for such items and for such value as have been specifically cleared by the DGTD/OG Committee. The value of import licence(s) issued under this credit should not exceed Y 8,500 million (CIF).

The rupee value of the import licence shall be determined with reference to the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) and prevailing on the date of issue of the import licence and indicated in the body of the import licence(s) as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)/74 dated the 6th June, 1974, issued by the CCI&E, which also enjoins that the Customs Authorities and the authorised dealers in foreign exchange will make debits to the value of the licence(s) at the exchange rate specified on the import licence(s). The licence will bear the superscription "Japanese Yen Credit No. ID-P. 14". The first and second suffix to the licence code will be "S/JC". This will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence to T.N.S.E.B., a copy of which should be endorsed to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section).

I(iii) Import licence(s) can be issued only in favour of INSEB on CIF basis.

I(iv) Depending on the convenience of TNSEB more than one import licence may be issued under this credit, but the total value must not exceed Y 8,500 million (CIF) as specified at (i) above.

I(v) The extension of the validity of the import licence, may on application by TNSEB, be granted upto 31st March, 1986. Request for further extension, if any, should be referred to the Department of Economic Affairs (Japan Section).

I(vi) Imports to be financed under the Credit are restricted to the list of goods and services attached to the import licence, duly attested by the licensing authorities.

I(vii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore be charged to the licence.

I(viii) Firm order must be placed on FOB basis on the Overseas supplier located in the countries mentioned in Annexure-I and sent to the Department of Economic Affairs (Japan section) within 4 months from the date of issue of the import licence. Freight and insurance charges will be payable in India in Indian rupees. "Firm orders" means purchase orders placed by the Indian Licencee on the overseas supplier duly signed by the letter or purchase contract

duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I(ix) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section) within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para I(viii) above cannot be placed within four months for valid reasons, the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within four months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of the import licence such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licensee. Only on production by the licensee of a letter from the licensing authorities sanctioning such extension will the authorised dealers and departmental authorities permit the facility of letter of authority for the establishment of letter of credit, acceptance of deposits of the rupee equivalent, etc. in respect of supply contracts entered into under the import licence.

I(x) All payments must be completed within 4 month from the expiry of the import licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian importer from the Overseas supplier. The contract should provide for the period of delivery of goods as follows :

".....months after the receipt of Letter of credit but to be completed latest by the end of.....".

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31st March, 1986.

#### Section II—Special points to be kept in view while negotiating a supply contract.

II(i) The FOB value of the contract should be expressed in Yen (Fraction of Yen should be omitted) and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian Rupees.

In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupees or in any other currency. The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II(ii) The main guidelines for procurement of goods and services under the OECF Yen Credit (Project Aid) are given in Annexure II. However, normally the procurement of goods and services should be made through Formal Open International Tendering and the following points should be borne in mind :—

- Invitations to bid shall have to be advertised in at least one newspaper of general circulation in India.
- Bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement but they should not be set so high as to discourage suitable bidders.
- Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

II(iii) In cases where Formal Open International Tendering is not considered appropriate the Fund will accept the following alternative procedures :—

- Where the importer has convincing reasons or maintaining a reasonable standardisation of his equipment.

(b) Where the number of qualified suppliers is limited.

(c) Where the amount involved in the procurement is so small that foreign firms clearly would not be interested or that the advantages of formal open international tendering would be outweighed by the administrative burden involved.

(d) Where, in addition to the cases (a), (b) and (c) above, the Fund deems it inappropriate to follow the formal open international tendering procedures or the Fund deems such procedure inapplicable, e.g., in case of emergency procurement.

In the above mentioned case the following procurement procedure may be applied in such a manner as to comply with the formal open international tendering procedures to the fullest possible extent as appropriate:

(i) Formal Selective International Tendering.

(ii) Informal International Competitive Procurement,

(iii) Direct Purchases from a single-supplier.

TNSEB should submit immediately, in triplicate, copies of all notices and instructions to bidders, the bid form, the proposed contract, specifications and drawings, reports of the analysis of bids, proposal for awards and all other documents relevant to bidding to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section) who will submit these documents to the OECF for its review as provided in para 1(2) of Schedule 5 of the Loan Agreement.

II(iv) The payment to the overseas supplier should be arranged through an irrevocable letter of credit to be opened by the Bank of India, Tokyo in their favour under DECF Yen Credit (Project Aid) No. ID-P. 14 for 1981-82 the details of which are given in Section VI below:

II(v) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II(vi) Eligibility of Supplier:

Suppliers shall be nationals of the eligible source countries or juridical persons incorporated and registered in the eligible source countries and controlled by nationals of the eligible source countries.

II(vii) Declaration in Contract:

The following statements of eligibility by the supplier shall be added to each contract.

"I, the undersigned, hereby certify that the goods to be supplied are produced in \_\_\_\_\_ (eligible source country).

I, the undersigned, further certify that to the best of my information and belief, the portion imported from the non-eligible source countries is less than thirty per cent (30%) in accordance with the following formula:

$$\frac{\text{Imported CIF Price} + \text{Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price}} \times 100$$

and

"I, the undersigned, hereby certify that \_\_\_\_\_ (Name of company) has been incorporated and registered in \_\_\_\_\_ (Name of eligible source country), and is controlled by nationals of the eligible source countries."

II(viii) Permissible imports from non-eligible source countries.

Financing of goods which contain materials originating from a non-eligible source country of countries may be made, provided that the imported portion is less than thirty per cent (30%) on an item-by-item basis in accordance with the following formulae:

$$\frac{\text{Imported CIF Price} + \text{Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price}} \times 100$$

Section III—Conditions to be incorporated in the supply contracts.

III(i) The following provisions should be specifically embodied in the supply contract:

(a) The contract is arranged in accordance with the Loan Agreement between the Government of India and the Overseas Economic Co-operation Fund of Japan (OECF) dated the 15th October, 1981 concerning the Yen Credit No. ID-P. 14 (Project Aid) for Lower Mettur Hydro electric Project on TNSEB and will be subject to the approval of Government of India and the Overseas Economic Co-operation Fund.

(b) Payments to the supplier shall be made through an irrevocable letter of Credit to be issued by the Bank of India, Tokyo, under the Loan Agreement No. ID-P. 14 dated 15th October, 1981 between the Government of India and the Overseas Economic Co-operation Fund of Japan (OECF).

(c) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents may be required under the Yen Credit arrangements by the Government of India on the one hand and the OECF on the other.

(d) Certificates (triplicate) in the forms indicated in II(vii).

III(ii) In case the supplier is located in Japan, the supply contract should contain a clause that the Japanese supplier agrees to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo, informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India at least four weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements could be made. In exceptional cases, where the Indian importers require it, this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV—Contract Approval by OECF.

IV(i) Within the stipulated period for placement of firm orders the licensee should forward 4 copies of the contract duly signed by both T.N.S.E.B. and Overseas suppliers supported by order confirmation in writing by the overseas supplier or their photo copies complete in all respects, together with two photo copies of the relevant valid import licence, to Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

IV(ii) The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

IV(iii) The Ministry of Finance (DEA) Japan Section will arrange to send one copy of the contract documents to the OECF for their approval for financing under Yen Credit No. ID-P. 14 (Project Aid) for Lower Mettur Hydro electric Project of TNSEB.

Section V—Payment to the overseas suppliers—Letter of Credit Procedure.

V(i) On receipt of the intimation of the contract approval from the OECF, by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Japan Section, TNSEB and the CAA&A will be informed of the same. Whereafter the TNSEB should approach the Controller of Aid Accounts & Audit, (hereinafter referred to as CAA&A) Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi with a request in the form attached as Annexure III for issue of a letter of authorisation. The CAA&A will issue a letter of authorisation as in the form attached as Annexure-IV addressed to the Tokyo Branch of the Bank of India for opening an irrevocable Letter of Credit as in the

form attached as Annexure-V (for physical Imports) or Annexure-VI (for services) in favour of the overseas supplier concerned. Copies of the Letter of Authorisation will be endorsed to the OECF, the Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India, and Japan section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

V(ii) On receipt of the letter of authority, the Bank of India, Tokyo, will establish an irrevocable letter of credit as per Annexure-V (applicable to physical imports) or VI (applicable to services) in favour of the overseas suppliers concerned and will also forward a copy of the same to the OECF, Embassy of India, Tokyo, the importer's bank in India and the CAA&A.

The above procedure of opening of letters of credit on the basis of the letters of authority from CAA&A would ipso facto apply to all such amendments to letter of authorisation/letter of credit as may become necessary due to contract amendment or otherwise.

V(iii) The overseas supplier shall, after effecting shipment of goods, present through his bankers the documents specified in the letter of credit to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the overseas supplier through his bankers and will thereafter obtain reimbursement of the said amount from the OECF.

V(iv) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for opening the letter of credit, for negotiations thereunder and charges, if any, of overseas supplier's bankers are to be borne by the overseas suppliers and hence not payable by the importer. Interest charges payable to the Bank of India, Tokyo for the period counting from the date of payment of the cost of imports by them to the overseas supplier to the date of reimbursement by the OECF shall be settled by the concerned importer's bank in India by remittances to the Bank of India, Tokyo through normal banking channel without affecting the Government of India's account.

#### Section VI—Responsibility for rupee deposit :

VI(i) The Bank of India, Tokyo will forward the negotiable shipping documents to the accredited bankers of importer as indicated in the Appendix to the relevant Letter of Authority and the bankers will in turn ensure that the rupee deposits are invariably made at RBI, New Delhi or S.B.I. Tis Hazari, Delhi before releasing the shipping documents. Interest charges on the rupee-equivalents of the Yen payments calculated @ 9 per cent per annum for the first 30 days and @ 15 per cent per annum for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the Overseas Supplier to the date of actual rupee deposit, have also to be deposited along with the principal payment, in terms of Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16th June, 1976. It should be noted that interest is chargeable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Overseas supplier and also the day on which rupee deposit is made in Government Account vide Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31st May, 1974 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12th October, 1976.

The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen payments made to the overseas suppliers will be the composite rate of exchange applicable to the date of payment which will be worked out in accordance with the method prescribed in Public Notices No. 109-ITC(PN)/74 dated 3rd August, 1974 and No. 8-ITC(PN)/76 dated 17th January, 1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances—843—Civil Deposits—Deposits for purchase etc. abroad—Purchase under credits/loan Agreements" Loans from the Government of Japan—7.6 Billion Yen Credit No. ID-P. 14 for Lower Mettur Hydro electric Project.

VI(ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi, or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30th August, 1968. No. 233-ITC(PN)/68

dated 24th October, 1968, No. 132-ITC(PN)/71 dated 5th October, 1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31st May, 1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12th October, 1976.

VI(iii) The concerned Bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, on account of service charges within seven days after such a demand is made by Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) while filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers/their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5th October, 1971 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the treasury Challans :—

- Ministry of Finance letter of authority No. and date.
- Amount of Yen currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.
- Date of payment to the overseas supplier.

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the letter of authorisation issued by him and also enclosing copies of the invoice and shipping documents.

NOTE : Importer's Bank in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A Ministry of Finance (OEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

VI(iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite 'S' Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

#### Section VIII—Miscellaneous provisions :

##### VIII(i) Reports on the utilisation of the import licence.

The importer should send a monthly report, after the letter of credit has been opened regarding shipments and payments made thereagainst and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

##### VIII(ii) Notifying Suppliers of Special Conditions.

The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

##### VIII(iii) Disputes :

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licensee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-III under "Terms of Payment". Provisions dealing with settlement of disputes should be included in the conditions of contract.

##### VIII(iv) Future Instructions :

The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Yen Credit Agreement (Project Aid) No. ID-P. 14 with the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).

##### VIII(v) Breach or violation :

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act

## VIII(vi) List of Annexures :

- Annexure-I List of eligible source countries.
- Annexure-II Broad Guidelines for Procurement.
- Annexure-III Request for issue of Letter of Authority.
- Annexure-IV Form of Letter of Authority.
- Annexure-V Form of Letter of Credit (Applicable to Physical Imports).
- Annexure-VI Form of Letter of Credit (Applicable to Services).

## ANNEXURE-I

## LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES

## A. Developing Countries and Territories

## (a1) Non-OPEC Developing Countries

## I. AFRICA, North of Sahara

Egypt  
Morocco  
Tunisia

## II. AFRICA, South of Sahara

Angola  
Botswana  
Burundi  
Cameroon  
Cape Verde Islands  
Central African Rep.  
Chad  
Comoro Islands  
Congo, People's Republic of Dahomey  
Equatorial Guinea (1)  
Ethiopia  
Gambia  
Ghana  
Guinea  
Ivory Coast  
Kenya  
Lesotho  
Liberia  
Malagasy Republic  
Malawi  
Mali  
Mauritania, Mauritius  
Mozambique  
Niger  
Portuguese Guinea  
Reunion  
Rhodesia  
Rwanda  
St. Helena and dep. (2)  
Sao Tome and Principe  
Senegal  
Seychelles  
Sierra Leone  
Somalia  
Sudan  
Swaziland  
Togo, Afars and Issas  
Togo  
Uganda  
Un. Rep. of Tanzania  
Upper Volta  
Zaire Republic  
Zambia

## III. AMERICA, North and Central

Bahamas  
Barbados

Belize  
Bermuda  
Costa Rica  
Cuba  
Dominican Republic  
El Salvador  
Guadeloupe  
Guatemala  
Haiti  
Honduras  
Jamaica  
Martinique  
Mexico  
Netherlands Antilles  
Nicaragua  
Panama  
St. Pierre & Miquelon  
Trinidad and Tobago

- (1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernando Po.
- (2) Including the following islands : Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gough.
- (3) Main islands, Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, St. Eustace, St. Martin (Southern part).

## AMERICA, North &amp; Central

—(Continued)

West Indies (Br.) n.i.e.  
(a) Associated States (1)  
(b) Dependencies (2)

## IV. AMERICA, South

Argentina  
Bolivia  
Brazil  
Chile  
Colombia  
Falkland, Islands  
French Guiana  
Guyana  
Paraguay  
Peru  
Surinam  
Uruguay

## V. ASIA, Middle East

Bahrain  
Israel  
Jordan  
Lebanon  
Qatar  
Syrian Arab Republic  
United Arab Emirates(3)  
Yemen Arab Republic  
Yemen, People's D.R.(4)

## VI. ASIA, South

Afghanistan  
Bangladesh  
Bhutan  
Burma  
India  
Maldives  
Nepal  
Pakistan  
Sri Lanka



VII. ASIA, Far East  
 Brunei  
 Hong Kong  
 Khmer Republic  
 Korea, Republic of  
 Laos  
 Macao  
 Malaysia  
 Phillippines  
 Singapore  
 Taiwan  
 Thailand  
 Timor  
 Viet-Nam, Rep. of  
 Viet-Nam Dem. Rep.

VIII. OCEANIA  
 Cook Islands  
 Fiji  
 Gilbert & Ellice Is.  
 French Polynesia (5)  
 Nauru  
 New Caledonia  
 New Hebrides (Br. and Fr.)  
 Niue  
 Pacific Islands (US) (6)  
 Papua New Guinea  
 Solomon Islands (Br.)  
 Tonga  
 Wallis and Futuna  
 Western Samoa

#### IX. EUROPE

Cyprus  
 Gibraltar  
 Greece  
 Malta  
 Spain  
 Turkey  
 Yugoslavia

- (1) Main Islands : Antigua, Dominica, Grenada, St. Kitts (St. Christopher), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent.
- (2) Main islands : Montserrat, Cayman, Turks and Caicos, and British Virgin Islands.
- (3) Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah and Ummal Quaiwain.
- (4) Including Aden and various sultanates and emirates.
- (5) Comprising the Society Islands (including Tahiti), the Austral Islands, the Tuamotu-Gambier Group and the Marquesas Islands.
- (6) Trust Territory of the Pacific Islands : Caroline Islands, Marshall Islands, and Marine Islands (except Guam)

#### (a2) Member of Association countries of OPEC

Algeria  
 Bolivia  
 Libyan Arab Republic  
 Gabon  
 Nigeria  
 Ecuador  
 Venezuela  
 Iran  
 Iraq  
 Kuwait  
 Qatar  
 Saudi Arabia

Abu Dhabi  
 Indonesia

#### ANNEXURE II

### MAIN GUIDELINES FOR PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES UNDER THE PROJECT LOAN AS FORMULATED BY O.E.C.F.

#### I. Advertising :

For all contracts subject to Formal Open International Tendering, invitations to bid shall be advertised in at least one newspaper of general circulation in India.

#### II. Bidding Documents and Contracts:

##### II-1. Bid Bonds or Guarantees :

Bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement but they should not be set so high as to discourage suitable bidders. Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

##### II-2. Conditions of Contract :

The conditions of contract should clearly define the rights and obligations of the importer and the contractor or supplier, and the powers and authority of the engineer, if one is employed by the importer, in the administration of the contract and any variations thereunder. In addition to the customary general conditions of contract, some of which are referred to in these Guidelines, special conditions appropriate to the nature and location of the project should be included.

##### II-3. Type and Size of Contract :

Contracts can be let on the basis of unit prices for work performed or items supplied or of a lump sum price, or a combination of both for different portions of the contract, according to the nature of the goods or services to be provided and the bidding documents should clearly state the type of contract selected.

Contracts based principally on the reimbursement of actual costs are not acceptable by the Fund except in exceptional circumstances.

Single contracts for engineering, equipment and construction to be provided by the same party ("Turnkey Contracts") are acceptable if they offer technical and economic advantages for the borrower country.

##### II-4. Eligible suppliers :

Exporters or suppliers whose goods and services are to be financed out of the proceeds of the Loan (hereinafter referred to as "the eligible supplier") shall be nationals of the eligible source countries satisfying the following conditions.

- (1) a majority of subscribed shares shall be held by nationals of the eligible source countries,
- (2) a majority of full-time directors shall be nationals of the eligible source countries; and
- (3) such juridical 'persons' shall be registered in the eligible source countries.

#### III-1. Contract Price :

- (a) The contract price should be stated in Japanese Yen provided, however, that the portion of the contract price which the contractor will spend in the borrower's country should be stated in the borrower's currency.

##### (b) Price Adjustment Clauses :

Bidding documents should contain a clear statement whether firm prices are required or escalation of the bid prices is acceptable.

A provision should be made for adjustment in the contract prices in the event changes occur in the

prices of the major cost constituents of the contract, such as labour and important materials.

The specific formula for price adjustments should be clearly defined in the bidding documents.

A ceiling on price adjustment should be included in contracts for the supply of goods, but it is not usual to include such a ceiling in contracts for civil works.

No price adjustments should normally be provided for goods to be delivered within one year.

The Guidelines do not attempt to identify the various methods by which contract prices may be adjusted.

#### (c) Insurance :

The bidding documents should state precisely the types of insurance to be provided by the successful bidder.

III-2. The contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian importer placed on the overseas supplier supported by order confirmation in writing by the overseas supplier, or their photo copies are also acceptable to the Fund.

III-3. The following statement of eligibility by the supplier shall be added to each contract.

"I(We) hereby state that my(our) company is an eligible supplier, as \_\_\_\_\_ per cent ( \_\_\_\_\_ %) of the shares are held by nationals of \_\_\_\_\_ (eligible source country), and \_\_\_\_\_ per cent ( \_\_\_\_\_ ) of the directors are nationals (eligible source country) and my (our) company has been registered in \_\_\_\_\_ (eligible source country)".

#### IV-1. Standards :

If national standard to which equipment or materials must comply are cited, the specifications should state that commodities meeting Japan Industrial Standard or other internationally accepted standards, which ensure an equal or higher quality than the standards mentioned, will also be accepted.

#### IV-2. Use of Brand Names :

Specifications should be based on performance capability and should only prescribe brand names, catalogue numbers, or products of specific manufacturer if specific spare parts are required or it has been determined that a degree of standardization is necessary to maintain certain essential features. In the latter case the specifications should permit offers of alternative commodities which have similar characteristics and provide performance and quality at least equal to those specified.

#### IV-3. Guarantees, performance Bonds and Retention Money:

Bidding documents for civil works should require some form of surety to guarantee that the work will be continued until it is completed. This surety can be provided either by a bank guarantee or by a performance bond, the amount of which will vary with the type and magnitude of the work, but should be sufficient to protect the borrower in case of default by the contractor. Its life, should extend sufficiently beyond completion of the contract to cover a reasonable warranty period. The amount of the guarantee or bond required should be defined in the bidding documents.

In contracts for the supply of goods it is usually preferable to have a percentage of the total payment held as retention money to guarantee performance than to have a bank guarantee or bond. The percentage of the total payment to be held as retention money and the conditions for its ultimate payment should be stipulated in the bidding documents. If, however, a bank guarantee or bond is preferred it should be for a nominal amount.

#### V. Liquidated Damage :

Liquidated damage clauses should be included in bidding documents when delays in completion or delivery will result

in extra cost, loss of revenues or loss of other benefits to the borrower. Provision may also be made for a bonus to be paid to contractors for completion of civil works contracts at or ahead of times specified in the contract when such earlier completion would be of benefit to the borrower.

#### VI. Force Majeure :

The conditions of the Contract included in the bidding documents should contain clauses, when appropriate, stipulating that a failure on the part of the parties to perform their obligations under the Contract shall not be considered a default under the Contract if such failure is the result of an even of force majeure (to be defined in the conditions of the Contract).

#### VII. Settlement of Disputes :

Provision dealing with the settlement of disputes should be included in the conditions of the Contract. It is desirable that the provisions should be based on "Rules of Conciliation and Arbitration" which have been prepared by the International Chamber of Commerce or on such other arrangements as may be mutually acceptable to the Indian Importer and the overseas supplier.

#### VIII. Language Interpretation :

Bidding documents should be prepared in English. If other language should be used in the bidding documents, English should be added to such documents and it is required to specify which is governing.

#### IX. Bid opening, Evaluation and Award of Contract :

##### IX-1. Time Interval between Invitation and submission of Bids :

The time allowed for preparation of bids will depend to a large extent upon the magnitude and complexity of the contract. Generally not less than 30 days should be allowed for international bidding. The time allowed, however, should be governed by the circumstances relating to each contract.

##### IX-2. Bid Opening procedures :

The date, hour and place for the latest receipt of bids and for the bid opening should be announced in the invitations to bid and all bids should be opened publicly at the stipulated time. Bids received after this time should be returned unopened. The name of the bidder and the total amount of each bid and of any alternative bids, if they have been requested or permitted, should be read aloud and recorded.

##### IX-3. Clarifications or Alternation of Bids:

No bidder should be permitted to alter his bid after the bids have been opened. Only clarifications not changing the substance of the bid may be accepted. The importer may ask any bidder for a clarification of his bid but should not ask any bidder to change the substance or the price of his bid.

##### IX-4. Procedures to be confidential :

Except as may be required by law, no information relating to the examination, clarification and evaluation of bids and recommendations concerning award should be communicated after the public opening of bids to any persons not officially concerned with these procedures until the award of a contract to the successful bidder is announced.

##### IX-5. Examination of Bids :

Following the opening, it should be ascertained whether material errors in computation have been made in the bids, whether the bids are fully responsive to the bidding documents, whether the required sureties have been provided, whether documents have been properly signed and whether the bids are otherwise generally in order. If a bid does not substantially conform to the specifications, or contains inadmissible reservations, or is not otherwise substantially responsive to the bidding documents, it should be rejected. A technical analysis should then be made to evaluate each responsive bid and to enable bids to be compared.

**IX-6. Post-qualification of Bidders :**

In the absence of prequalifications, the borrower should be determined whether the bidder whose bid has been evaluated the lowest has the capability and financial resources effectively to carry out the contract concerned. If the bidder does not meet that test, his bid should be rejected.

**IX-7. Evaluation and Comparison of Bids :**

Bid evaluation must be consistent with the terms and conditions set forth in the bidding documents. In addition to the bid price, adjusted to correct arithmetical errors other factors such as the time of completion of construction or the efficiency and compatibility of the equipment, the availability of service and spare parts, and the reliability of construction methods proposed should be taken into consideration. To the extent practicable these factors should be expressed in monetary terms according to criteria specified in the bidding documents. The amount of escalation for price adjustments, if any, included in the bids should not be taken into consideration.

The currency or currencies in which the price offered in each bid would be paid by the borrower if that bid were accepted should be valued in terms of a single currency selected by the borrower for comparison of all bids and stated in the bidding documents. The rates of exchange to be used in such valuation should be the selling rates published by an official source, and applicable to similar transactions on the day bids are opened unless there should be a change in the value of currencies before the award is made. In such cases the exchange rates at the time of the decision to notify the award to the successful bidder should be used.

**IX-8. Rejection of Bids :**

Bidding documents usually provide that borrowers may reject all bids. However, all bids should not be rejected and new bids invited on the same specifications solely for the purpose of obtaining lower prices in the new bids, except in cases where the lowest evaluated bid exceeds the costs estimates by a substantial amount. Rejection of all bids may also be justified when (a) bids are not responsive to the intent of the bidding documents, or (b), there is a lack of competition. If all bids are rejected, the borrower should review the cause or causes justifying the rejection and either consider revision of the specifications or modification in the project (or amounts of work on items called for in the original invitation (o bids), or both. In special circumstances, after consultation with the Fund, the borrower may negotiate with one or two of the lowest bidders to try to obtain a satisfactory contract.

**IX-9. Award of Contract :**

The Award of a contract should be made to the bidder whose bid has been determined to be the lowest evaluated bid and who meets the appropriate standards of capability and financial resources. Such bidder should not be required, as a condition of award, to undertake responsibilities on commodities not stipulated in the specifications or to modify his bid.

**ANNEXURE III****REQUEST FOR ISSUE OF THE LETTER OF AUTHORITY****DATE :**

To,

The Controller of Aid Accounts & Audit,  
Ministry of Finance,  
Department of Economic Affairs,  
U.C.O. Bank Building, 1st Floor,  
Parliament Street,  
New Delhi-110001.

Subject.—Import of \_\_\_\_\_ from Japan under the Yen Credit No. ID-P. 14 (Project Aid).

Sir,

In connection with the import of \_\_\_\_\_ from \_\_\_\_\_ under the above mentioned Yen Credit No. ID-P. 14

(Project Aid) we furnish the following particulars to enable you to issue the Letter of Authority to the \_\_\_\_\_ (name of the Bank) which should be the same as given in (n) below for opening a letter of credit in favour of the overseas supplier concerned.

- (a) Name and Address of the Indian importer.
- (b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.
- (c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or Formal Open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.
- (d) Brief description of the goods.
- (e) Origin of the goods.
- (f) Percentage of the import components from non-eligible source countries, if any.
- (g) Gross FOB value of contract (in Yen).
- (h) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any.
- (i) Net FOB value (In Yen) for which the Letter of Authority is required.
- (j) Number and date of the contract with overseas suppliers.
- (k) Name and Address of the Overseas Supplier :
  - (i) Nationality.
  - (ii) Percentage of the shares held by Nationals of the eligible source countries.
  - (iii) Nationality of the representative and/or President of the supplier.
  - (iv) Percentage of Directors who are nationals of eligible source countries.
- (l) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.
- (m) Expected date of completion of deliveries.
- (n) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).
- (o) Shipment instructions (indicate if trans-shipment/part-shipment permitted or not permitted).
- (p) Name and address of the Importer's bank in India.
- (q) Whether any contract(s) under the said licence has been placed and notified to the Japanese authorities, and if so, the No., date and value of each such contract and the reference of the Ministry of Finance under which it has been notified to the O.E.C.F.

**ANNEXURE IV**

(Letter of Authority Form)

No. F.

**GOVERNMENT OF INDIA****MINISTRY OF FINANCE****(Department of Economic Affairs)**

New Delhi, the

To

The Bank of India,  
Tokyo Branch,  
Tokyo (Japan).

Subject.—Import under Yen Credit (Project Aid)—Loan Agreement No. ID-P. 14—Issue of Letter of Authority for opening Letter of Credit.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 25th March, 1980 entered into with your Bank,

you are hereby authorized to open irrevocable Letter of Credit for an amount not exceeding Yen..... favouring M/s..... as per attached details.

A copy each of the letter of credit opened by your Bank may be endorsed to the importer's Bank, to the OECF Embassy of India, Tokyo and to us.

Payments to the suppliers in terms of the letter of credit will be made initially out of your own funds. After payments, you must claim immediately reimbursements of the amounts paid by furnishing necessary documents to the OECF.

Interest charges payable to you, for the time lag between the dates of payment by you to the supplier and the date of its reimbursement by the OECF, shall be settled by you with the concerned importer's Bank in India through normal banking channels without affecting the Government of India's account. The other banking charges including those on account of opening, maintenance and for the operation of the Letter of Credit as also those connected with handling negotiating documents and charges of overseas suppliers bankers if any, are to be borne by the Overseas Suppliers and hence not payable by the importer and may therefore be recovered from the Suppliers directly. As such no reimbursement of such charges is to be claimed from the OECF.

As and when any payment is made by you and reimbursement is made to you, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry.

This Letter of Authority is intended for opening of L/C favouring the overseas suppliers. Subsequent amendments to L/C or further fresh L/C against this authorisation may not be acted upon in the absence of a specific authority from this Ministry.

This Letter of Authority will remain valid upto.....

Yours faithfully,

(ACCOUNTS OFFICER)

Copy forwarded to:—

1. Importer.....with reference to their letter No.....dated.....

2. Importers' Banker..... They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amounts disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to overseas suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC(PN)/76, dated 17th January, 1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @ 9 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 15 per cent per annum for period in excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier/date of reimbursements to Bank of India and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Government Account, is also required to be deposited into the Government of India Account in terms of Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16th June, 1976. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Overseas Suppliers and also the date on which rupee deposit is made into Government Account. Any change in this rate will be intimated if and when made. It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi. In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 184-ITC(PN)/68, dated 30th August, 1968, 233-ITC(PN)/68, dated 24th October, 1968, 132-ITC(PN)/71, dated 5th October, 1971, No. 74-ITC(PN)/74, dated 31st May, 1974 and No. 103-ITC(PN)/76, dated 12th October, 1976. The head of Account to be credited is "K-Deposits & Advances—843—Civil Deposits—Deposit for purchases etc.

abroad under Purchases under Credit/Loan Agreements"—Loans from the Government of Japan—7.6 billion Yen Credit (Project Aid) No. ID-P. 14 for 1981-82.

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi, or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71, dated 5th October, 1971, should be sent by them to the address given below along with a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24th October, 1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases full particulars of the rupee equivalents deposited should be furnished to this Department.

Interest charges payable to the Bank of India, Tokyo for the time lag between the dates of payment to the supplier and the date of its reimbursement to the Bank of India, Tokyo by the OECF shall be settled directly by you with the Bank of India, Tokyo through normal banking channels without affecting Government of India's account.

3. The Director, Loan Department-II, Overseas Economic Cooperation Fund, Takebashi Godo Building, 4-1, Ohtemachi 1-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100, Japan.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary, Japan Section, Ministry of Finance Department of Economic Affairs, New Delhi.

Accounts Officer.

ANNEXURE V

Form OECF-LC I

Irrevocable Letter of Credit

(Applicable for goods)

Date:

To .....

(Name and address of the Supplier)

This Letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No. .... dated ..... between (Borrower) and THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No.....in your favour for account of..... for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of..... (Say yen ..... ) available by your drafts at sight for full invoice value drawn on us, to be accompanied by the following documents:

Signed commercial invoice in

Full set of clean on board ocean bills of lading made out to order and blank endorsed and marked "Freight and "Notify

Other documents

evidencing shipment of [brief description of goods to be shipped referring to Contract No.....(if any)] From ..... to ..... Partial shipments are.....permitted. Transshipment is.....permitted.

Bills of lading must be dated not later than..... Drafts must be presented for negotiation not later than.....

All drafts and documents under this credit must be marked "Drawn under ..... irrevocable credit No. .... dated ..... and Import Reference No(s) ..... (if any)".

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290".

#### SPECIAL INSTRUCTIONS TO THE NEGOTIATING BANK

1. After obtaining the reimbursement for our payments from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the above-mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with instructions issued by the negotiating bank.
2. The negotiating bank must forward the drafts and one complete set of documents to us together with the certificate stating that the remaining documents have been airmailed direct to .....
3. All banking charges under this credit are for the account of the importer/supplier.

Yours faithfully,

.....  
(A Commercial Bank)

By: .....  
(Authorised Signature)

#### PAYMENT TERMS

This payment terms constitutes an integral part of our Letter of Credit No.

##### I. Initial Payment

Amount : Y  
being % of the total  
contract price.

Required documents:  
Latest presentation date :

##### II. Intermediate Payment (if any)

Amount: Y  
being % of the total  
contract price.

Required documents:  
Latest presentation date :

##### III. Payment against Shipping Documents

Amount : Y  
being % of the total  
contract price.

Note :—This attached sheet is not required in case of full payment against shipping documents.

1239 GI/81—4

#### ANNEXURE VI

#### Form OECF-LC. II

#### Irrevocable Letter of Credit (Applicable for Services)

Date:

To

.....

.....  
(Name and address of  
the supplier).

This letter of Credit has been  
issued pursuant to Loan  
Agreement No.....  
Dated .....  
between Borrower and THE  
OVERSEAS ECONOMIC  
COOPERATION FUND.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No..... in your favour for account of for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of ..... (Say Yen ..... ) available by beneficiary's drafts at sight for full statement value drawn on us.

To be accompanied by the required documents, in accordance with the Payment Schedule attached hereto, ..... concerning (Contract No. .... with regard to .... Project). Drafts must be presented for negotiation not later than.....

All drafts and documents must be marked "Drawn under irrevocable credit No ..... dated

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "UNIFORM Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290".

#### SPECIAL INSTRUCTIONS TO THE NEGOTIATING BANK

1. After receipt of the original Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority) in accordance with the form attached hereto, payment(s) under this credit must be made in accordance with the Payment schedule stipulated in the sheet attached hereto. In case of the initial payments, the beneficiary's Statement is required instead of the above-mentioned statement of Performance.
2. After obtaining the reimbursement for our payment from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the above mentioned Loan Agreement we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with the instructions issued by the negotiating bank.
3. A copy of the document as mentioned in item 1 above and the drafts shall be sent to us immediately after the receipt thereof.
4. All banking charges under this credit are for the account of the importer/supplier.

Yours faithfully,

.....  
(A Commercial Bank),

By : .....  
(Authorised Signature).

**PAYMENT SCHEDULE:****Statement of Performance**

This payment schedule constitutes an integral part of our Letter of Credit No.

Date:  
Ref. No.

**I. Initial Payment**

Amount : Y  
being % of the total contract price  
Required documents : beneficiary's Statement.

Latest presentation date :

**II. Progress Payment**

Aggregate amount : Y  
being % of the total contract price to be paid as follows :

Amount due Latest presentation date :

1st Instalment : Y

2nd Instalment : Y

Required document : a copy of statement of Performance issued (*Borrower or its designated authority*), a form of which is attached hereto.

To  
(Name and address of the supplier)

Re: Letter of Credit No. dated  
issued by in favour of  
for Y. concerning  
Project under Loan Agreement No.

I, the undersigned, representing (*Borrower*), hereby issue a Statement of Performance to entitle ..... to receive the sum of Y..... (Yen..... only) from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the Payment Terms stipulated in the Contract No ..... dated ..... between ..... and .....  
(Borrower)

By:  
(Authorised Signature)

Special Instructions :

The details of the actual performance shall be stated in the sheet attached hereto.

MANI NARAYANSWAMY, Chief Controller,  
Imports & Exports.